RNI NO. CHHHIN/2010/36902 वर्ष : 15, अंक 4 मार्च 2025 - विक्रम संवत 2082 निः शुल्क वितरण हेतु

मासिक पत्रिका

छत्तीसगढ़

जनमन

बजट से मिली रफ्तार

प्रगति

की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

जनजन तक पहुँचेगा सुशासन तिहार

मोदी बोले रजत से स्वर्ण की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

स्थानीय परीक्षार्थियों को बड़ी राहत

शुल्क माफ, लौटाई जाएगी राशि

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, सरगुजा/बस्तर/बिलासपुर की परीक्षाएं देने वालों को लाभ

राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होंगे उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी।

इससे सीनियर कैंडिडेट की परीक्षा में उपस्थिति का प्रतिशत बढ़ेगा, वहीं नॉन सिरियस केन्डीडेट और इनइलिजिबल केन्डीडेट परीक्षा फॉर्म नहीं भरेंगे।

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से जुड़ने के लिए Q.R. Code स्कैन करें

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

नई परियोजनाएँ बदलेंगी विकास का चेहरा

हम छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। संयोग से यह साल अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार 2025 को 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मना रही है। हमने बहुत से लक्ष्य तय किए हैं और लगातार सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में शामिल हो गया है जहाँ शत–प्रतिशत रेल नेटवर्क का विद्युतीकरण हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान 33700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें मुख्य रूप से रेलवे परियोजना 1188 करोड़ की, राष्ट्रीय राजमार्ग परियाजनाएँ 954.36 करोड़ की, विद्युत परियोजनाएँ 568 करोड़ की तथा शिक्षा परियाजनाएँ 119.65 करोड़ की शामिल हैं।

अप्रैल माह की शुरुआत राहतों से हुई है। पेट्रोल पर वैट घटने और ई–वे बिल की सीमा दोगुनी होने का लाभ लोगों को मिल रहा है। नक्सलवाद पर हम लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। इससे निराश नक्सलियों ने अब वार्ता की पेशकश की है। हालाँकि हमारी नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति–2025 का परिणाम है कि बीजापुर जिले में कुल 50 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में अब तक 2200 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और सैकड़ों ने आत्मसमर्पण किया है साथ ही अब तक 350 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। दूसरी ओर हमने बस्तर के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। अबूझमाड़ के हांदावाडा गाँव में बिजली पहली बार पहुँची है तथा नक्सल प्रभावित धरमाराम में

पहली बार पीएम योजना का आवास बना है। दंतेवाड़ा के गीदम में हम 299.85 करोड़ की लागत से नया मेडिकल कॉलेज भवन निर्माण करने जा रहे हैं। बस्तर की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का बहुरंगी उत्सव "बस्तर पंडुम 2025" की गौरवशाली शुरुआत भी हमने की।

औद्योगिक निवेश से राज्य में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं, इसे ध्यान में रखकर मैंने कर्नाटक राज्य का दौरा किया। बेंगलुरू में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट के तहत प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की तथा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए आमंत्रित किया। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए तीन लाख करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं, जिससे आने वाले समय में, देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका होगी। जीएसटी संग्रह में छत्तीसगढ़ पूरे देश में अव्वल आया है, जाहिर है इसमें राज्य के करोड़ों लोगों का सहयोग मिला है। छत्तीसगढ़ में 3497 करोड़ की नई गैस एवं पेट्रोलियम परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं जिससे आम जन सीधे लाभान्वित होंगे।

हमारी सरकार प्रदेश के हर वर्ग के उत्थान और समृद्धि के लिए संकल्पित है। जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 67 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है साथ ही वनोपज के वैल्यू एडिशन को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। वुडबॉल नेशनल चैंपियनशिप' में छत्तीसगढ़ के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया है। इसी तरह तीर्थयात्रा के इच्छुक बुजुर्ग श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने 19 तीर्थस्थानों के लिए 'मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना' का शुभारंभ किया है।

देश के महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉ.भीमराव अम्बेडकर, गुरु तेग बहादुर एवं वल्लभाचार्य की जयंती पर उन्हें शत–शत नमन. भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2082 आपके लिए मंगलमय हो।

-विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

RNI Regi.-CHHHIN/2010/36902

हिंदी मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमन

रायपुर, वर्ष : 15, अंक 4, मार्च 2025-विक्रम संवत 2082

मुद्रक एवं प्रकाशक
डॉ. रवि मित्तल

संपादक
जवाहर लाल दरियो

संपादकीय सलाहकार
आलोक देव

संपादन सहयोग
पंकज गुप्ता

डिजाइनर
सुरेंद्र देवांगन

संधारण एवं प्रसार
जनसंपर्क संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

संपर्क
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर

पत्रिका छत्तीसगढ़ जनमन के इस अंक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कृपया QR कोड स्कैन करें।

E-Mail : chhattisgarhjanman@gmail.com

नोट : पत्रिका में प्रकाशित सभी लेख, आलेख व समाचार की जिम्मेदारी ''संपादक'' की होगी। तथ्य एवं आँकड़े परिवर्तनशील होते हैं, इस पत्रिका में उनका उल्लेख केवल सांकेतिक है। पुष्टि तथा विस्तृत जानकारियों के लिए संबंधित विभागों से संपर्क किया जा सकता है। किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र रायपुर (छत्तीसगढ़) होगा।

सुर्खियाँ

4 विकसित छत्तीसगढ़ को मिला सौगातों...

छत्तीसगढ़ बजट वर्ष 2025-26

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट समावेशी, नवाचारयुक्त और तेज विकास को...

18 25 वर्ष की विकास यात्रा...

विकास की सौगात

छत्तीसगढ़ ने अपने रजत जयंती वर्ष में विकास की एक नई गाथा लिख...

26 दुनिया ने देखी बस्तर की अद्भुत कला...

बस्तर पंडुम

बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा को मंच प्रदान करने के लिए पहली बार...

हिंदी मासिक पत्रिका
छत्तीसगढ़ जनमन

44 देश का पॉवर हब बनने को तैयार छत्तीसगढ़...

ऊर्जा का नया गढ़

प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार की ओर से राज्य के विकास और गुडगवर्नेंस को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च माह में प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इन्वेस्टर्स समिट ने इस बात के पूर्ण संकेत दे दिए हैं कि पॉवर के मामले में...

32 विकास की धड़कन पूरे लय से धड़क ...

खनिज विकास

देश का मिनरल हार्ट छत्तीसगढ़ अपनी लय पकड़ चुका है। खनिज व खनन...

38 संस्कारों की धरती, साहित्य की नगरी...

शहर की कहानी

अगर छत्तीसगढ़ की आत्मा को महसूस करना हो तो कदम रखिए...

24 छत्तीसगढ़ की धरती से उठी शब्दों की...

सर्वोच्च सम्मान

मैंने जीवन में बहुत पास से देखा है– पेड़ कैसे खड़े...

36 कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को...

वैश्विक दर्जा

बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज...

58 गर्मी में ठंडक देने वाला छत्तीसगढ़ी स्वाद

हमर कलेवा

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खानपान के...

विकसित छत्तीसगढ़ को मिला सौगातों का पिटारा

विकास की नई दिशा और गति

प्रGATI
CG बजट 2025-26

। जनमन रिपोर्ट ।

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अपना दूसरा बजट प्रस्तुत करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में यह बजट समावेशी, नवाचारयुक्त और तेज विकास को प्राथमिकता देता है। यह न केवल राज्य के रजत जयंती वर्ष का प्रतीक है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में इसे 'अटल निर्माण वर्ष' के रूप में मनाने की भी घोषणा की गई है। यह बजट राज्य को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की मजबूत नींव रखता है और विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाता है।

"यह बजट वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य के विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद मजबूत करता है। इससे प्रदेश को तेजी से विकास की राह मिलेगी। इसमें कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही छत्तीसगढ़ को इंडस्ट्रियल और आईटी हब के रूप में विकसित करने की ठोस पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हम छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। बदहाल राजकोष और कुशासन की विरासत के बावजूद हमने सुधार कर जनकल्याण की योजनाएँ दोबारा शुरू कीं और विकास को गति दी है। इसमें "ज्ञान के लिए गति" थीम के तहत गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए नवाचारी योजनाएँ लाई गई हैं। सुशासन, आधारभूत संरचना, तकनीक और औद्योगिक विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया यह बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य की दिशा तय करता है।"

विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

06 लाख 35 हजार 917 करोड़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

1.65 लाख करोड़ रुपये का बजट किया गया पेश

26 हजार 341 करोड़ पूंजीगत व्यय

पिछले वर्ष यानी 2024-25 का बजट "GYAN"—गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी—के समावेशी विकास पर केंद्रित था। इस वर्ष सरकार ने "GATI" के माध्यम से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, औद्योगिक विकास और गुड गवर्नेंस को नई ऊँचाइयों तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है। इस रणनीति के तहत, छत्तीसगढ़ 2030 तक आत्मनिर्भर और विकसित राज्य बनने के लिए अपनी विकास यात्रा को तेज करेगा।

GATI के चार स्तंभ और छत्तीसगढ़ की प्रगति

G गुड गवर्नेंस
GOOD GOVERNANCE

- शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ लाई जाएँगी।
- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे नागरिकों तक पहुँचे, इसके लिए ई-गवर्नेंस को मजबूत किया जाएगा।
- भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन और जनहितकारी नीतियों को लागू कर जनता को सेवाएँ सरल और प्रभावी तरीके से प्रदान की जाएँगी।

घोषणा

- सरकारी वित्तीय संचालन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए अगली पीढ़ी की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली का कार्यान्वयन।
- ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से सरकारी फाइलों के ऑनलाइन निपटान की व्यवस्था।
- अटल निगरानी पोर्टल (मुख्यमंत्री डैशबोर्ड), जिससे सरकारी परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी की जा सकेगी।
- खनिज ऑनलाइन 2.0 के माध्यम से ऑनलाइन खनिज प्रबंधन प्रणाली का उन्नयन।
- सरकारी योजनाओं और सेवाओं में नागरिकों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना।

A इंफ्रास्ट्रक्चर
ACCELERATING INFRASTRUCTURE

- सड़कों, पुलों, लॉजिस्टिक्स, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा।
- सरकार ने रेलवे कनेक्टिविटी, नए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर के निर्माण की भी घोषणा की है।
- स्मार्ट शहरों के विकास के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर बनेंगे।

घोषणा

- पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ (कुल बजट का 16%), जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक।
- शहरी निकायों (ULB) के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए 750 करोड़ का प्रावधान।
- बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं अधोसंरचना विकास के लिए 170 करोड़।
- मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना के लिए 100 करोड़।
- जगदलपुर, बिलासपुर व अंबिकापुर में हवाई अड्डों का विकास।
- पुलिस स्टेशनों को सुदृढ़ करने के लिए 70 करोड़ आवंटित।
- नए अग्निशमन स्टेशनों की स्थापना एवं क्षमता वृद्धि के लिए 44 करोड़।

T प्रौद्योगिकी
TECHNOLOGY

- शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
- शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में स्मार्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुधार किया जाएगा।
- डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से युवाओं को टेक्नोलॉजी-आधारित नौकरियों के लिए तैयार किया जाएगा।

घोषणा

- न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 37 करोड़।
- डायल 100/112 आपातकालीन सेवाओं के लिए 125 करोड़।
- ई-धरती परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 48 करोड़।
- वाणिज्यिक कर विभाग में व्यापार खुफिया इकाई के लिए 41 करोड़।
- स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना के लिए 40 करोड़।
- प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के डिजिटलीकरण हेतु 24 करोड़।
- अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली (CCTNS) के संचालन व रखरखाव के लिए 25 करोड़।
- डिजिटल गवर्नेंस की स्थापना के लिए 9 करोड़।
- परिवहन विभाग में वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन हेतु 8 करोड़।

I औद्योगिक विकास
INDUSTRIAL GROWTH

- इस्पात, बिजली उत्पादन, सीमेंट और वस्त्र उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियाँ लागू की जाएँगी।
- 'मेक इन छत्तीसगढ़' पहल के तहत स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा।
- निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की रणनीति बनाई गई है।
- सरकार निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, जिससे लाखों नए रोजगार सृजित होंगे।

घोषणा

- औद्योगिक विकास एवं व्यापार को सुगम बनाने के लिए बी.आर.ए.पी (Business Reform Action Plan) के तहत एकल खिड़की प्रणाली का कार्यान्वयन।
- सी.एस.आई.डी.सी (Chhattisgarh State Industrial Development Corporation) में ERP एप्लिकेशन का कार्यान्वयन।
- "इन्वेस्ट छत्तीसगढ़" कार्यक्रम के तहत राज्य में निवेश बढ़ाने की पहल।
- रोजगार मूलक औद्योगिक नीति को प्रोत्साहन।
- उद्योग विभाग का बजट पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक।

विष्णु देव सरकार के प्रयास और विकसित छत्तीसगढ़ की योजना

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने सत्ता में आने के बाद से ही राज्य को तेज गति से विकसित करने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। इस बजट में इन प्रयासों को और सशक्त बनाने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने अपने विकास मॉडल को चार मुख्य स्तंभों पर आधारित किया है–गुड गवर्नेंस, अधोसंरचना विकास, टेक्नोलॉजी और औद्योगिक प्रगति, जिसे GATI के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सरकार का विजन केवल शहरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाओं को पहुँचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में नई सौगातों के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह छत्तीसगढ़ को आधुनिक बुनियादी ढाँचे, डिजिटल प्रगति और औद्योगिक समृद्धि की ओर तेजी से ले जाना चाहती है।

GATI के माध्यम से छत्तीसगढ़ की प्रगति

इस बजट के माध्यम से सरकार ने यह साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ अब सिर्फ विकास की ओर नहीं, बल्कि विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। GATI रणनीति के तहत राज्य को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति और औद्योगिक समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। छत्तीसगढ़ अब सिर्फ एक उभरता हुआ राज्य नहीं, बल्कि भारत के सबसे प्रगतिशील राज्यों में से एक बनने की ओर अग्रसर है। यह बजट प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समर्पित है और एक नए, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक सशक्त कदम है।

5 मुख्य सौगातें

प्रमुख आर्थिक संकेतक और कर प्रावधान

छत्तीसगढ़ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में राज्य की आर्थिक मजबूती, पूँजीगत व्यय में वृद्धि और कराधान में राहत जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। यह बजट राजकोषीय अनुशासन और सतत विकास को संतुलित करते हुए छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ बजट 2025-26 राज्य की आर्थिक स्थिरता, राजकोषीय अनुशासन और समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूंजीगत व्यय में इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी वृद्धि से यह स्पष्ट होता है कि सरकार राज्य के बुनियादी ढाँचे और औद्योगिक विकास को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर सुधारों और व्यापारिक सहूलियतों के जरिए सरकार व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा दे रही है। इस बजट के माध्यम से छत्तीसगढ़ आधुनिक बुनियादी ढाँचे, निवेश अनुकूल नीतियों और नागरिक-केंद्रित शासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे यह निश्चित रूप से विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा।

बजट 2025-26: एक दृष्टि में

विवरण	2024-25 (अनुमानित करोड़ में)	2025-26 (अनुमानित करोड़ में)	% वृद्धि
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	5,67,880	6,35,918	12%
राजस्व प्राप्ति	1,47,500	1,65,100	12%
कुल व्यय	1,47,446	1,65,000	12%
राजस्व व्यय	1,24,840	1,38,196	11%
पूँजीगत व्यय	22,300	26,341	18%
पूँजीगत व्यय/कुल बजट	15%	16%	-
पूँजीगत व्यय/GSDP	3.93%	4.14%	-
राजस्व अधिशेष	1,060	2,804	-
राजकोषीय घाटा	-16,296	-18,900	-

राजकोषीय संकेतक

- **सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP):** वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का GSDP 12% की वृद्धि के साथ 6,35,918 करोड़ होने का अनुमान है।
- **प्रति व्यक्ति आय:** वित्त वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,62,870 रहने की उम्मीद है, जो 9% की वृद्धि दर्शाती है।
- **अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान:**
  - कृषि क्षेत्र का GSDP में योगदान 17% है।
  - औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 48% है।
  - सेवा क्षेत्र का योगदान 35% है।
- **राजस्व में वृद्धि:** राज्य सरकार द्वारा बिना किसी नए कर लगाए राजस्व में 11% वृद्धि हासिल करने का अनुमान है।
- **पूँजीगत व्यय:** वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूँजीगत व्यय 26,341 करोड़ प्रस्तावित है, जो राज्य के गठन के बाद अब तक का उच्चतम स्तर है। यह कुल बजट का 16% और GSDP का 4.14% है।
- **राजस्व अधिशेष:** वित्त वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ का राजस्व अधिशेष 2,804 करोड़ रहने की संभावना है।
- **राजकोषीय घाटा:** राज्य का कुल राजकोषीय घाटा 22,900 करोड़ होगा, जिसमें से 4,000 करोड़ विशेष सहायता के रूप में पूँजीगत व्यय के लिए रखा गया है। इसका शुद्ध राजकोषीय घाटा 18,900 करोड़ होगा, जो GSDP का 2.97% है और FRBM अधिनियम के 3% सीमा के भीतर है।

प्रगति CG बजट 2025-26

प्रमुख घोषणाएँ

शिक्षा

₹50 करोड़
24 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों का उन्नयन।

₹50 करोड़
आईटीआई का उन्नयन।

₹25 करोड़ विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (CSVTU) का अधोसंरचना विकास।

₹06 करोड़ 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज भवनों की स्थापना।

₹34 करोड़ 12 नर्सिंग कॉलेज भवनों की स्थापना।

₹277 करोड़
पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PMSHRI) योजना के तहत स्कूल अधोसंरचना का आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण।

₹212 करोड़
कॉलेज भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के लिए।

- बलरामपुर व राजनांदगाँव में 500-सीटर आवासीय स्कूल भवन की स्थापना।

ग्रामीण विकास

₹845 करोड़ - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।

₹119 करोड़ - मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना।

₹100 करोड़ - मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत जल निकासी प्रणाली युक्त सड़कें।

कर सुधार और व्यापारियों के लिए राहत

राज्य सरकार ने कर प्रणाली को सरल बनाने और छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं:

- **ई-वे बिल सीमा में वृद्धिः** व्यापारियों के लिए ई-वे बिल की अनिवार्य सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जिससे छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
- **पुराने वैट विवादों का निपटाराः**
  - 10 साल से अधिक पुराने लंबित मामलों में 25,000 तक की वैट देनदारी को माफ करने का निर्णय।
  - इस पहल से 40,000 से अधिक व्यापारियों को लाभ होगा और 62,000 से अधिक मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।
- **एकमुश्त निपटान योजना (OTS Scheme):** राज्य सरकार ने उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए One Time Settlement (OTS) योजना की घोषणा की है।
- **स्टांप शुल्क पर राहतः** अचल संपत्ति लेन-देन पर स्टांप शुल्क उपकर हटाया जाएगा, जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा।

प्रमुख घोषणाएँ और विकास के नए आयाम

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 में कृषि, बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक घोषणाएँ की हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की सरकार ने इस बजट को "अटल निर्माण वर्ष" के तहत प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक मजबूत आधारशिला के रूप में प्रस्तुत किया है। यह बजट न केवल किसानों, महिलाओं, युवाओं और गरीबों के सशक्तीकरण को प्राथमिकता देता है, बल्कि औद्योगिक विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नागरिक सुविधाओं को भी नई ऊँचाइयों पर ले जाने की योजना प्रस्तुत करता है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट हर वर्ग को साथ लेकर समावेशी विकास की ओर बढ़ने का प्रयास है। कृषि और ग्रामीण विकास, बुनियादी ढाँचे का विस्तार, औद्योगिक प्रगति, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तीकरण के माध्यम से राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। इस बजट में समाज के हर वर्ग को लाभ देने की कोशिश की गई है—किसानों के लिए समर्थन मूल्य, युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास, व्यापारियों के लिए कर सुधार, महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा, आदिवासी और वनवासी समुदायों के लिए आर्थिक सशक्तीकरण, और नागरिकों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार। यह बजट राज्य की आर्थिक वृद्धि को नई ऊँचाइयों पर ले जाने के साथ-साथ 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कृषि और ग्रामीण विकास

- कृषक उन्नति योजना के लिए **10,000 करोड़** का प्रावधान, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता और नई तकनीकों का लाभ मिलेगा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत **8,500 करोड़**, जिससे गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराए जाएँगे।
- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए **4,500 करोड़**, जिससे कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- 5 HP तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए **3,500 करोड़,** जिससे किसानों की सिंचाई लागत में कमी आएगी।
- जल संसाधन विभाग को **3,800 करोड़,** जिसमें से 700 करोड़ नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत **845 करोड़,** जिससे गाँवों को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिलेगी।
- प्रधानमंत्री जनमन सड़क निर्माण योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए **500 करोड़**।

शहरी विकास और बुनियादी ढाँचा

- सबके लिए आवास योजना के तहत **875 करोड़,** जिससे शहरी क्षेत्रों में घरों का निर्माण होगा।
- नगर पंचायतों और नगर पालिकाओं में रिंग रोड निर्माण के लिए **100 करोड़,** जिससे यातायात सुगम होगा।
- लोक निर्माण विभाग को **2,000 करोड़,** राज्य में नई सड़कों के निर्माण के लिए पहली बार इतना बड़ा आवंटन किया गया है।
- नवा रायपुर में एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) के उन्नयन और संचालन के लिए **40 करोड़**।
- नवा रायपुर में नए पॉवर सब स्टेशन के लिए **20 करोड़,** जिससे बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ

- आयुष्मान योजना के लिए **1,500 करोड़**, जिससे लाखों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएँ मिलेंगी।
- रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना के लिए **47 करोड़**।
- सरोना (रायपुर) और जनकपुर – मनेंद्रगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल, तखतपुर (बिलासपुर) में 50 बिस्तरों वाला महिला एवं बाल अस्पताल, मनेंद्रगढ़ में मनोरोग अस्पताल का निर्माण।
- राखी, सारिया व कटघोरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन।
- रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (UPHC) का विस्तार।

प्रGATI
CG बजट 2025-26

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

₹1,850 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।

₹10 करोड़ रायपुर में ए.आर.टी. केंद्र की स्थापना।

₹1,500 करोड़ शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना।

₹20 करोड़ रायपुर मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीदी।

₹10 करोड़ डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का विस्तार।

₹35 करोड़ डॉ. भीमराव अंबेडकर मेमोरियल अस्पताल रायपुर में मशीनों की खरीदी।

₹186 करोड़ - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन।

₹182 करोड़ आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना।

₹13 करोड़ मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना।

₹132 करोड़ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना योजना।

₹13 करोड़ सिकल सेल संस्थान की स्थापना।

₹21 करोड़ छत्तीसगढ़ आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया सेवा योजना।

₹100 करोड़ मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना।

शिक्षा और युवाओं के लिए अवसर

- 17 नए नालंदा पुस्तकालयों की स्थापना, जिससे छात्रों को आधुनिक अध्ययन सुविधाएँ मिलेंगी।
- 25 कॉलेजों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए **75 करोड़**।
- शहरी क्षेत्रों में 150 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1200 आँगनबाड़ी भवनों के निर्माण के लिए **40 करोड़**।
- स्काउट्स और गाइड्स के 19वें राष्ट्रीय जंबूरी कार्यक्रम के लिए बजटीय प्रावधान।

सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार

- बलौदा बाजार - भाटापारा, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर-चाँपा और जशपुर में 5 नए साइबर पुलिस थाना।
- कोरबा, जांजगीर-चाँपा और सूरजपुर में 3 नए महिला पुलिस थानों की स्थापना।

आदिवासी और वनवासी कल्याण

- तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा **5,500 रुपये** का भुगतान।
- तेन्दूपत्ता संग्राहकों के लिए "चरण पादुका" योजना के तहत **50 करोड़** का प्रावधान।
- मत्स्य उत्पादन, डेयरी, पोल्ट्री, बकरी पालन, सूअर पालन आदि के लिए **200 करोड़**।
- मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के लिए **200 करोड़**, जो पिछले बजट से 300% अधिक है।

हवाई सेवाओं का विस्तार

- बिलासपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर से उड़ान सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए 40 करोड़ की वीजीएफ (Viability Gap Funding) योजना।
- जगदलपुर व अंबिकापुर हवाई अड्डे के अधोसंरचना विकास के लिए प्रावधान।

नई पहल से विकास को नई दिशा

छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2025-26 में कई नई योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है, जो राज्य के विकास को तेज गति देने के साथ-साथ तकनीकी नवाचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, डिजिटल अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों को मजबूती प्रदान करेंगी। छत्तीसगढ़ सरकार की यह नई पहल राज्य की समग्र और सतत विकास रणनीति का हिस्सा हैं। ये न केवल डिजिटल और भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करेंगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को भी सुनिश्चित करेंगी।

डिजिटल कनेक्टिविटी और संचार

- **मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना:** बस्तर और सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वीजीएफ (Viability Gap Funding) के माध्यम से बजटीय प्रावधान।
- सभी ग्राम पंचायतों में यूपीआई (डिजिटल भुगतान) को बढ़ावा देने के लिए बजट प्रावधान, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था डिजिटल होगी।
- भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए वित्तीय आवंटन, जिससे पारदर्शिता और किसानों की सुविधा बढ़ेगी।

प्रगति CG बजट 2025-26

महिला एवं बाल विकास

₹5,500 करोड़ महतारी वंदन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता।

₹800 करोड़ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसमें लखपति महिला और ड्रोन दीदी योजना शामिल।

₹133 करोड़ एससीए योजना के तहत कामकाजी महिला छात्रावास का निर्माण।

₹100 करोड़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

₹100 करोड़ मिशन वात्सल्य के तहत बाल संरक्षण की पहल।

₹50 करोड़ हाई स्कूल की छात्राओं को साइकिल वितरण।

₹40 करोड़ मुख्यमंत्री कन्यादान योजना।

₹20 करोड़ हिंसा प्रभावित महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर (सखी)।

₹13 करोड़ शुचिता योजना के तहत सैनिटरी उत्पादों की उपलब्धता।

₹10 करोड़ पालना योजना के तहत परित्यक्त और अनाथ बच्चों की देखभाल।

₹9 करोड़ महिला सशक्तीकरण केंद्र की स्थापना।

परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर

- **मुख्यमंत्री परिवहन योजना:** उन ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ जनसंख्या घनत्व कम होने के कारण सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ग्राम पंचायत से ब्लॉक और जिला स्तर तक परिवहन सुविधा विकसित की जाएगी।
- राज्य की राजधानी क्षेत्र (SCR) कार्यालय की स्थापना और रायपुर-दुर्ग मेट्रो लाइन का सर्वेक्षण।
- नगर निगमों के डीपीआर आधारित विकास के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नवा रायपुर में 200 करोड़ रुपये की लागत से एक प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस-वाइल्डलाइफ-वाटर टूरिस्ट सुविधा विकसित करने की योजना।

कृषि और सहकारिता

- 500 नई सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा, जिससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- केंद्र सरकार की पीएसएस (PSS) योजना के तहत पहली बार दालों और तिलहन की खरीद के लिए बजट प्रावधान।
- महानदी - इंद्रावती और सिकासार - कोडार नदियों को जोड़ने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा, जिससे सिंचाई और जल प्रबंधन को नया आयाम मिलेगा।

स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएँ

- राज्य के सभी ब्लॉकों में सिकल सेल स्क्रीनिंग केंद्रों की स्थापना का पहला चरण, जिससे सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम और उपचार को बढ़ावा मिलेगा।
- नवा रायपुर में मेडिसिटी की स्थापना, जिससे राज्य को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त होंगी।

शिक्षा और कौशल विकास

- नवा रायपुर में एजुकेशन सिटी की स्थापना, जिससे उच्च शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्य में एक और राष्ट्रीय संस्थान के रूप में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना, जिससे फैशन डिजाइनिंग और टेक्सटाइल सेक्टर में नए अवसर मिलेंगे।
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के छत्तीसगढ़ चैप्टर की स्थापना, जिससे प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े युवाओं को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।

CG बजट 2025-26

डीएमएफ, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तरह, राज्य में एक समर्पित विशेष ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की स्थापना, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा।
- डीएमएफ (जिला खनिज निधि) के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- विभागीय सुधारों के प्रतिस्पर्धी सूचकांक (Competitive Index) के आधार पर प्रोत्साहन देने की योजना।

मीडिया और व्यापारिक समुदाय के लिए पहल

- पत्रकारों के एक्सपोजर विजिट और पत्रकार संघ कार्यालय के नवीनीकरण के लिए बजटीय प्रावधान, साथ ही पत्रकार सम्मान निधि की राशि को दोगुना किया जाएगा।
- नवा रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन।

जनजातीय विकास

₹220 करोड़ नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता।

₹50 करोड़ प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना।

₹30 करोड़ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान।

₹25 करोड़ पाम ऑयल की खेती को प्रोत्साहन।

₹221 करोड़ अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार।

₹400 करोड़ आदिवासी विकासखंडों में अंत्योदय योजना के तहत चना वितरण।

कृषि

₹600 करोड़ – दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना।

₹50 करोड़ डेयरी समग्र विकास परियोजना।

₹50 करोड़ कृषि पंपों का विद्युतीकरण।

लोक निर्माण विभाग (PWD)

₹403 करोड़ – मुख्य जिला सड़कें।

₹109 करोड़ – राज्य राजमार्ग।

₹574 करोड़ - बड़े पुलों का निर्माण।

₹100 करोड़ - रिंग रोड/बायपास निर्माण।

₹500 करोड़ - न्यूनतम सेवा के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण।

प्रगति को गति देकर छत्तीसगढ़ को महाशक्ति बनाने वाला बजट

छत्तीसगढ़ को सँवारने का संकल्प लेने वाली विष्णु सरकार के कार्यकाल का दूसरा बजट विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना को साकार करने का प्रतिबिंब है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार की प्रतिबद्धता का उद्घोष निरुपित होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश सरकार जनता से किए गए वादों को क्रांतिकारी निर्णयों के ज़रिए जिस तीव्रता से पूरा कर रही है, वह छत्तीसगढ़ की नई दिशा और दशा की मजबूत नींव है। इस बजट में विकास की आकांक्षाओं और जनसरोकारों के बीच संतुलन बैठाते हुए संसाधनों की जिम्मेदार व्यवस्था की गई है, जिससे यह साफ़ है कि आने वाला समय छत्तीसगढ़ के लिए नए युग की शुरुआत लेकर आएगा। वित्तीय लिहाज से देखा जाए तो यह छत्तीसगढ़ की जीडीपी को रफ्तार देने के साथ-साथ लोगों की आय बढ़ाने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के अवसरों से भरा हुआ है।

प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत किया गया यह बजट सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की नव-निर्माण गाथा का अगला अध्याय है। यह बजट प्रदेश की प्रगति को गति देकर उसे एक "मॉडल स्टेट" बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

बजट में की गई घोषणाओं में आम जनता के जीवन को सरल बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। पंजीयन के 20 मॉडल केंद्र, हक त्याग शुल्क को केवल 500 रुपए में सीमित करना जैसे प्रावधानों से लोगों को सीधी राहत मिलेगी। सीएम सुशासन फैलोशिप योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान कर सरकार ने युवाओं को नीति निर्माण से जोड़ने का अभिनव प्रयास किया है। इससे प्रशासनिक सोच में नवाचार आएगा और युवाओं को सशक्त भागीदारी का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही सीएम एक्सीलेंसी अवार्ड की घोषणा भी प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक कदम है।

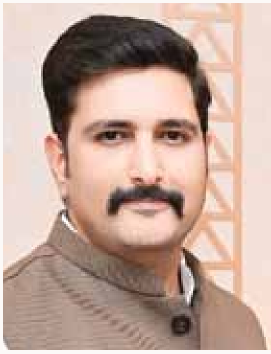

अमित चिमनानी

राजस्व वृद्धि की बात करें तो राज्य अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। राज्य की खुद की आय 76 हजार करोड़ रुपये आँकी गई है जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है। केंद्र की मोदी सरकार से 65 हजार करोड़ रुपये की सहायता का अनुमान है जो कि पिछले वर्ष से 13 प्रतिशत अधिक है। यह स्पष्ट करता है कि केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं।

इतना ही नहीं वित्तीय दबावों के बावजूद सरकार ने बजट का 16 प्रतिशत हिस्सा पूँजीगत व्यय के लिए रखा है जो बुनियादी ढाँचे को मजबूत करेगा और रोजगार के नए अवसरों का निर्माण करेगा। सिंचाई, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की घोषणा इस बात का प्रमाण है कि सरकार दूरदृष्टि से काम कर रही है। मेरा यह मानना है कि पत्रकार साथियों के लिए की गई घोषणाएँ बेहद सराहनीय हैं। सरकार ने पत्रकार सम्मान निधि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार करने, रायपुर प्रेस क्लब भवन के नवीनीकरण एवं विस्तार तथा पत्रकार एक्सपोजर विजिट जैसे कदमों से मीडिया जगत को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। यह केवल आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि पत्रकारिता के गौरव और गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक ठोस पहल है। साथ ही यह बजट जन-आकांक्षाओं, सुशासन और समावेशी विकास का दस्तावेज है। यह सरकार की दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आने वाला समय छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध प्रदेश के रूप में स्थापित करेगा।

लेखक पूर्व सलाहकार, महालेखाकार छत्तीसगढ़ व राजनीतिक मामलों के जानकार हैं।

बजट 2025-26: मुख्य विशेषताएँ

- आधारभूत संरचना को बल – पूँजीगत व्यय को प्राथमिकता देकर बुनियादी ढाँचे के विकास पर जोर।
- स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार –
  - कुनकुरी (जिला जशपुर) में नया मेडिकल कॉलेज।
  - डॉ. भीमराव आंबेडकर अस्पताल, रायपुर में उन्नत कार्डियक संस्थान का आधुनिकीकरण।
  - मेडिकल कॉलेज अस्पताल, रायपुर में निःसंतान दंपतियों के लिए ए.आर.टी. (IVF) सुविधा।
  - सरकारी अस्पतालों में एम.आर.आई. और सी.टी. स्कैन मशीनों के लिए प्रावधान।
- रोजगार और शिक्षा –
  - सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती में तेजी।
  - स्कूल, कॉलेजों में शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति का प्रथम चरण।
  - आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों का आधुनिकीकरण।
- औद्योगिक विकास – उद्योग विभाग का बजट पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना अधिक।
- पर्यटन को बढ़ावा – बस्तर और सरगुजा में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नई होमस्टे नीति।
- धार्मिक और सांस्कृतिक पहल – रामलला दर्शन और तीर्थ यात्रा योजना के लिए विशेष प्रावधान।
- कृषि और डेयरी विकास – राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी.) के सहयोग से राज्य में डेयरी सेक्टर को सशक्त बनाने की योजना।
- खेल और आयोजन –
  - बस्तर ओलंपिक, बस्तर मड़ई, नया रायपुर मैराथन, गोल्फ टूर्नामेंट आदि के लिए बजट प्रावधान।
- ऊर्जा क्षेत्र में सुधार –
  - पी.एम. सूर्यघर योजना और पी.एम. कुसुम योजना का प्रभावी क्रियान्वयन।
- सुरक्षा एवं प्रशासनिक सुधार –
  - राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (SISF) का गठन, सी.आई.एस.एफ. की तर्ज पर।
- कर्मचारियों के हित में पहल –
  - सरकारी कर्मचारियों को 53% महँगाई भत्ता (D.A.)।
  - पेंशन फंड बनाने के लिए विशेष प्रावधान।
- विकास और स्थिरता – छत्तीसगढ़ विकास एवं स्थिरता कोष की स्थापना।
- शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार – बलरामपुर और राजनांदगाँव में नया प्रयास संस्थान की स्थापना।

प्रGATI CG बजट 2025-26

सामाजिक कल्याण

₹1,000 करोड़ - घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए सब्सिडी।

₹420 करोड़ - मुख्यमंत्री पेंशन योजना।

₹250 करोड़ - प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।

₹200 करोड़ - राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना।

₹125 करोड़ सुखद सहारा योजना।

₹26 करोड़ - दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजनाएँ।

₹30 करोड़ - दिव्यांगजन शैक्षणिक संस्थानों के लिए।

खेल और युवा

₹150 करोड़ राज्य छात्रवृत्ति योजना।

₹115 करोड़ केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना।

₹50 करोड़ छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना।

₹47 करोड़ सीएम कौशल विकास योजना।

पर्यटन

₹15 करोड़ - सीएम तीर्थ दर्शन योजना।

₹15 करोड़ - 21 जिला परिवहन कार्यालयों में स्वचालित ड्राइविंग ट्रैक।

₹170 करोड़ - 15 साल से पुराने वाहनों के प्रतिस्थापन की योजना।

25 वर्ष की विकास यात्रा

रजत से स्वर्ण की ओर बढ़ेगी- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ दौरे पर सौंपे 33,700 करोड़ के विकास प्रकल्प

जनमन रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ ने अपने रजत जयंती वर्ष में विकास की एक नई गाथा लिख दी है। बिलासपुर की ऐतिहासिक धरती पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 33,700 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर राज्य को विकास के पथ पर और अधिक सशक्त किया। यह क्षण केवल योजनाओं की शुरुआत नहीं था बल्कि उन करोड़ों सपनों को वास्तविकता में बदलने की ओर एक ऐतिहासिक कदम भी था। नवरात्र और नववर्ष के पावन संयोग पर जब तीन लाख गरीब परिवार अपने नए घरों में प्रवेश कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को "मानवता का महापर्व" बताया। उन्होंने कहा कि ये घर केवल चारदीवारें नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता, गरिमा और नए जीवन की शुरुआत हैं। इनमें से अधिकांश घर महिलाओं के नाम पर हैं जिन्हें पहली बार संपत्ति में स्वामित्व मिला है।

प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की मातृभूमि माता महामाया, माता कौशल्या और भक्त माता कर्मा की गौरवगाथा का स्मरण करते हुए इसे देवी संस्कृति की जीवंत धरा बताया। उन्होंने श्रद्धा, समर्पण और शक्ति के इस प्रदेश को नवरात्र की विशेष शुभकामनाएँ दीं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि इन विकास परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं, बल्कि परिवर्तन है। इनमें आवास, सड़क, रेलवे, शिक्षा, गैस पाइपलाइन, बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार शामिल है। उन्होंने कहा कि इनसे राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की नई संभावनाएँ जन्म लेंगी।

आदिवासी समाज के प्रति विशेष संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री ने 'धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान' और 'पीएम जनमन योजना' के तहत 80,000 करोड़ के निवेश का उल्लेख किया। इससे राज्य के 7,000 से अधिक आदिवासी गाँवों में मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ देश के पूर्ण विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन चुका है। राज्य में वर्तमान में लगभग 40,000 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएँ चल रही हैं। उन्होंने 'पीएम सूर्य घर योजना' की शुरुआत का जिक्र करते हुए बताया कि सरकार हर घर को बिजली उत्पादक बना रही है, जिससे आम जन को आय भी होगी और बिजली भी मुफ्त मिलेगी।

...जब पीएम को सीएम ने भेंट किया कोसा सिल्क

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय विरासत से सजी कोसा सिल्क की हस्तनिर्मित शॉल भेंट की। इस शॉल में बाइसन हॉर्न माड़िया नृत्य और टोड़ी वाद्ययंत्र की कढ़ाई समेत राज्य की सांस्कृतिक विविधता और शिल्पकला की जीवंत झलक है। यह भेंट केवल वस्त्र नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, जनजातीय गौरव और लोकपरंपरा का प्रतीक बनकर प्रधानमंत्री तक पहुँची।

भारत के सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक है छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ जिसे 'धान का कटोरा' कहा जाता है, आज भारत के सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक बन रहा है। इस उड़ान को और ऊँचाई देने का कार्य किया प्रधानमंत्री मोदी ने, जब उन्होंने बिलासपुर की ऐतिहासिक भूमि से 33,700 करोड़ की 50 से अधिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

यह केवल योजनाओं का शुभारंभ नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के हर गाँव, हर आदिवासी, हर महिला और हर युवा के सपनों का साकार रूप है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

हमने इसे बनाया है, अब इसे और आगे बढ़ाएँगे

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और विश्वास की बहाली की मिसालें देते हुए उन्होंने सुकमा और दंतेवाड़ा के स्वास्थ्य केंद्रों, बस्तर ओलंपिक, एकलव्य मॉडल स्कूलों और विद्या समीक्षा केंद्र जैसे प्रयोगों की सराहना की। साथ ही मेडिकल व इंजीनियरिंग की हिंदी में पढ़ाई को 'नव भारत की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय' बताया। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं वर्षगाँठ और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती वर्ष से जोड़ते हुए प्रधानमंत्री ने इसे अटल निर्माण वर्ष घोषित किया और कहा कि "हमने इसे बनाया है, अब इसे और आगे बढ़ाएँगे।"

प्रधानमंत्री ने राज्य के हर कोने में विकास का उजियारा फैलाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ अब केवल खनिजों की भूमि नहीं, बल्कि आत्मबल, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक है। अगले 25 वर्षों में हम इसे भारत के अग्रणी राज्यों की पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे।

महत्वपूर्ण घोषणाएँ और परियोजनाएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत

- 3 लाख गरीब परिवारों को नए पक्के घर
- महिलाओं के नाम पर संपत्ति का अधिकार
- आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री बोले - ये घर केवल दीवारें नहीं, यह गरिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक हैं।

रेल परियोजनाएँ

- छत्तीसगढ़ देश के पूर्ण विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाले अग्रणी राज्यों में शामिल
- 40,000 करोड़ की चल रही रेल परियोजनाएँ
- कनेक्टिविटी व रोज़गार को मिलेगा बूस्ट

पीएम सूर्य घर योजना

- सोलर रूफटॉप से हर घर बनेगा बिजली उत्पादक
- बिजली मुफ्त और आमदनी भी आम जन के लिए दोहरा लाभ

जनजातीय विकास

- धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान
- पीएम जनमन योजना के तहत 80,000 करोड़ का निवेश
- 7,000 से अधिक गाँवों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएँ

संस्कृति और संवेदना

पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन की शुरुआत छत्तीसगढ़ की तीन माताओं – माता महामाया, माता कौशल्या और भक्त माता कर्मा – के चरणों में नमन से की। उन्होंने कहा: "छत्तीसगढ़ देवी संस्कृति की धरा है, जहाँ श्रद्धा भी है, शक्ति भी है और सेवा की भावना भी।" उन्होंने यह भी कहा कि राज्य का रजत जयंती वर्ष, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मशती वर्ष से जुड़कर एक "अटल निर्माण वर्ष" बन गया है। "अटल जी ने यह राज्य बनाया, अब इसे हम मिलकर सशक्त बनाएँगे।"

शांति और विश्वास का नया युग

- नक्सल क्षेत्रों में बनी स्वास्थ्य सुविधाएँ
- अब इलाज गाँव तक पहुँचा
- बस्तर ओलंपिक, एकलव्य विद्यालय, विद्या समीक्षा केंद्र
- शिक्षा और खेल में नई ऊर्जा
- मेडिकल-इंजीनियरिंग की हिंदी में पढ़ाई
- भाषाई समावेशिता का ऐतिहासिक निर्णय

यह भी कहा

- छत्तीसगढ़ अब केवल खनिजों की भूमि नहीं, बल्कि आत्मबल और समृद्धि का प्रतीक है
- अगले 25 वर्षों में यह राज्य भारत के अग्रणी राज्यों की कतार में खड़ा होगा
- केंद्र और राज्य मिलकर छत्तीसगढ़ की हर आकांक्षा को पूरा करेंगे

प्रधानमंत्री जनमन योजना बनी आत्मसम्मान की छत

बिलासपुर के मोहभट्ठा में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दल्लु राम बैगा से पूछा – "पक्का मकान बन गया है?" तो उनका मुस्कराते हुए जवाब आया – "हां, बन गया है।" यह संवाद केवल सवाल-जवाब नहीं, बल्कि करोड़ों गरीबों की उम्मीदों और सरकार की प्रतिबद्धता का जीवंत प्रतीक था। प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान के अंतर्गत जनमन योजना ने छत्तीसगढ़ के तीन लाख परिवारों को उनके सपनों का आशियाना दिया है। इन परिवारों को अब कच्ची झोपड़ियों के बदले पक्के घर मिले हैं, जो सिर्फ ईंट और छत नहीं, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के प्रतीक हैं। प्रधानमंत्री ने मंच से तीन विशेष पिछड़ी जनजातियों के हितग्राहियों – बीजापुर की सोमारी पुनेम, कबीरधाम के दल्लु राम बैगा और जशपुर के पहाड़ी कोरवा जगतपाल राम – को स्वयं चाबी सौंपकर उनके नवनिर्मित घरों का गृहप्रवेश कराया। ये सभी कभी असुरक्षित, असुविधाजनक झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन अब उनके पास खुद का सुरक्षित और सुविधाजनक पक्का घर है। इन आवासों के निर्माण के लिए दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता, मनरेगा के तहत मजदूरी, और अन्य योजनाओं के ज़रिए रसोई गैस, बिजली और शौचालय जैसी जरूरी सुविधाएँ दी गई हैं।

जशपुर के जगतपाल कहते हैं – "अब मेरा परिवार बारिश, अंधेरे और जंगली जानवरों के डर से मुक्त है। ये सिर्फ दीवारें नहीं, हमारे सपनों की बुनियाद हैं।"

बीजापुर की सोमारी कहती हैं – "पति के निधन के बाद मैंने सपनों से मुँह मोड़ लिया था, लेकिन आज इस घर में वह सपना फिर से जी उठा है।"

अब पटरी पर दौड़ेगा नया रायपुर का सपना

अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अब अपने नये विस्तार की ओर तेज रफ्तार से अग्रसर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिलासपुर के मोहभट्ठा में आयोजित ऐतिहासिक समारोह के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर नया रायपुर को रेल नेटवर्क से जोड़ा, जो राज्य के लिए एक बड़ा बुनियादी और भावनात्मक क्षण बन गया। अब रायपुर और नवा रायपुर का राजधानी रेल क्षेत्र के दायरे में आ चुका है। सस्ती, सुलभ और सुंदर यात्रा का यह नया अध्याय है, जिसकी शुरुआत विष्णु देव सरकार के प्रयासों से शुरू हो चुकी है।

अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस मेमू ट्रेन की विशेषताएँ

- थ्री-फेज़ तकनीक से सुसज्जित ट्रेन
- ऊर्जा दक्षता, उच्च गति और आरामदायक सफर का अद्वितीय मेल

लोगों ने कहा- अब नया रायपुर आना आसान

अब ऑफिस जाने में वक्त और पैसा दोनों की बचत होगी। यह ट्रेन नया रायपुर के विकास को नई दिशा देगी।"
रवि साहू, मंत्रालय कर्मचारी

स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा, हमने तो पहले ही टिकट बुक कर लिया है।"
नेहा वर्मा, छात्रा

प्रत्येक कोच आधुनिक

- सौंदर्यपूर्ण इंटीरियर
- कुशन वाली आरामदायक सीटें
- बड़ी खिड़कियाँ और स्लाइडिंग दरवाजे
- मोबाइल चार्जिंग सॉकेट
- GPS आधारित डिजिटल डिस्प्ले और लाउडस्पीकर सिस्टम (PAPIS)
- CCTV सुरक्षा प्रणाली
- पर्यावरण-अनुकूल बायो-टॉयलेट्स

ऐसे होगा फायदा

- रायपुर रेलवे स्टेशन से अब मंदिर हसौद, नया रायपुर सीबीडी, केंद्री होते हुए अभनपुर तक रेल सेवा उपलब्ध होगी।
- यह ट्रेन सेवा खासतौर पर मंत्रालय, सचिवालय, और शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत लोगों के लिए वरदान साबित होगी।
- दैनिक आवागमन अब मात्र 10 रुपए में संभव – यह सुविधा सामान्य नागरिकों, विद्यार्थियों और शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है।

राज्य को मिली 4 नई रेल परियोजनाएँ 2,695 करोड़ की सौगात

प्रधानमंत्री ने 4 पूरी हो चुकी रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, वहीं 7 नई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। यह छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा, विशेषकर आदिवासी और दूरस्थ इलाकों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में मददगार होगा।

डबल इंजन की सरकार पटरियों ने पकड़ी रफ्तार

8741
करोड़ के खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी

यह खास है इस प्रोजेक्ट में

- **8741** करोड़ की लागत
- **278** किमी का है रूट
- **615** किमी पटरी बिछेगी
- **21** नए स्टेशन का होगा निर्माण
- **48** बड़े ब्रिज बनेंगे
- **349** माइनर ब्रिज बनेंगे
- **14** फ्लाईओवर बनेंगे
- **184** अंडरपास का होगा निर्माण
- **06** जिले जुड़ेंगे इस परियोजना से

| जनमन रिपोर्ट |

छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार की वजह से विकास की पटरियों ने रफ्तार पकड़ ली है। छत्तीसगढ़ का रेलवे बजट अब 22 गुना बढ़कर लगभग 6900 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 2014 के बाद छत्तीसगढ़ में रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 1,125 किमी नए ट्रैक बने हैं, जो कि दुबई के पूरे रेलवे नेटवर्क से ज्यादा है। इसी कड़ी में 4 अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18658 करोड़ की लागत से चार मल्टीट्रेकिंग परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। खास बात यह है कि इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ को विशेष स्थान दिया गया है। ये परियोजनाएँ महाराष्ट्र, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में चालू होंगी। 1,247 किलोमीटर लंबी इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ में एक नई लाइन, महाराष्ट्र में लाइन का दोहरीकरण और ओड़िशा में अतिरिक्त लाइनों का निर्माण शामिल है। एक्सपट्र्स का कहना है कि इन प्रोजेक्ट्स की वजह से एक ओर जहाँ कनेक्टिविटी में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर लॉजिस्टिक्स लागत में भी कमी आएगी। महत्वपूर्ण पहलू यह है कि परियोजना के निर्माण के दौरान बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। एक अनुमान के मुताबिक 379 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन इन प्रोजेक्टस के निर्माण के दौरान होगा।

केंद्रीय कैबिनेट की ओर से मंजूर खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल प्रोजेक्ट के बारे में रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ की रेल कनेक्टिविटी को बदलने वाला है । इस प्रोजेक्ट पर 8741 करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे पूरे छत्तीसगढ़ को एक छोर से दूसरे छोर तक कवरेज मिलेगा । रेल मंत्री ने कहा कि खरसिया-परमलकसा 5वीं-6वीं रेल लाइन छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क की नई धमनी की तरह है। यह ओड़िशा की सीमा से महाराष्ट्र की सीमा तक रेल नेटवर्क की सुविधा प्रदान करेगी।

छत्तीसगढ़ के लोगों ने जिन उम्मीदों के साथ डबल इंजन की सरकार बनाई है, उसे पूरा करने का काम भारतीय रेल कर रही है। इस प्रोजेक्ट में 278 किलोमीटर रूट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियाँ बिछाई जाएँगी। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा।

अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में रेलवे से जुड़ा हजारों करोड़ का काम हो रहा है। नई परियोजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जिले जुड़ते हैं। खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना जैसी महत्त्वपूर्ण सौगात से छत्तीसगढ़ के विकास को नई गति मिलेगी। यह रेल परियोजना जांजगीर-चाँपा, सक्ती, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग और राजनांदगाँव जैसे प्रमुख जिलों को जोड़ेगी। इससे इन जिलों को नए अवसर मिलेंगे। लोगों को रोजगार मिलेगा। बलौदाबाजार और जांजगीर उद्योगों के लिए नया हब बनकर उभरेंगे। यह क्षेत्र लाइमस्टोन (चूना पत्थर) से समृद्ध है। रेल संपर्क बेहतर होने से यहाँ सीमेंट उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

डबल इंजन सरकार का असर

- छत्तीसगढ़ में रेलवे का कुल निवेश 47 हजार करोड़ से अधिक है
- 32 स्टेशनों का पुनर्निर्माण हो रहा है, और इन्हें पूरी तरह नया बनाया जा रहा है ।
- दल्लीराजहरा से रावघाट नई लाइन पूरी होने वाली है
- रावघाट से जगदलपुर रेल लाइन के डीपीआर बनाने का काम लगभग पूरा हो गया है
- गेवरा-पेन्ड्रा रोड नई लाइन पर भी तेजी से काम चल रहा है
- राजनांदगाँव से नागपुर तीसरी लाइन, झारसुगड़ा से बिलासपुर चौथी लाइन, रायपुर-केन्द्री-धमतरी से अभनपुर-राजिम लाइन का गेज कन्वर्जन करके ब्रॉड गेज बनाया जा रहा है
- राजनांदगाँव से डोंगरगढ़ चौथी लाइन, जगदलपुर से कोरापुट की डबलिंग, धरमजयगढ़ से कोरबा नई लाइन, अनूपपुर से अंबिकापुर के दोहरीकरण के लिए पर्याप्त फंड दिया गया है।

देश के बड़े रेल प्रोजेक्ट्स में से एक, जुड़ेंगे आधा दर्जन जिले

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी पीसी में कहा कि यह भारत के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में से एक है। इससे छत्तीसगढ़ के रायगढ़, जांजगीर चाँपा, बिलासपुर, बलौदा बाजार, दुर्ग और राजनांदगाँव जैसे जिले जुड़ेंगे। इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर निवासियों को दिक्कत न हो इसके लिए 5 रेल फ्लाईओवर भी निर्मित किए जाएँगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में 278 किलोमीटर रूट में 615 किलोमीटर लंबी पटरियाँ बिछाई जाएँगी। इस रूट के निर्माण के बाद 8 से ज्यादा मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इस रेल नेटवर्क के निर्माण से करीब 22 करोड़ लीटर डीजल बचेगा और रेलवे को लगभग 2500 करोड़ रुपये के डीजल की बचत होगी। रेल मंत्री ने कहा कि भगवान राम के वनवास के दौरान माता शबरी के प्रसंग से जुड़े लक्ष्मी नारायण मंदिर का भी इस रेल नेटवर्क से संपर्क स्थापित होगा। बलौदा बाजार और खरसिया जैसे सीमेंट उत्पादन के बड़े इंडस्ट्रियल हब भी इस नेटवर्क से जुड़ेंगे।

बायपास सिस्टम अपना रहा रेलवे

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रेलवे अब बायपास पद्धति को अपना रहा है। इसके तहत मालगाड़ी को शहर के बाहर से निकालने पर जोर दिया जा रहा है। वहीं यात्री गाड़ियों को शहर के अंदर एंट्री दी जाएगी। इस रेल लाइन के निर्माण के दौरान भी इस पर फोकस रहेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत कोसा सिल्क के उत्पादन वाले इलाके भी रेल लाइन के जरिए जुड़ेंगे। इसके चलते 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार उत्पन्न होगा।

सीएम ने जताई खुशी, पीएम को दिया धन्यवाद

वर्तमान में चल रहे रेलवे के कार्य व नई परियोजना को मिली स्वीकृति पर सीएम विष्णु देव साय ने खुशी जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया है और कहा कि इस परियोजना से नया रायपुर तक सीधी रेल लाइन से राजधानी का संपर्क मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों से और बेहतर होगा। परियोजना से माल परिवहन तेज होगा, जिससे उद्योगों की लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी। इससे कृषि उत्पादों, खनिजों और निर्माण सामग्री के ट्रांसपोर्ट को भी बल मिलेगा। इससे नया रायपुर के विकास को नई दिशा और रफ्तार मिलेगी। वहीं केन्द्रीय आवासन एवं शहरी राज्यमंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मंजूर की गई इस परियोजना के लिए खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

सर्वोच्च सम्मान

छत्तीसगढ़ की धरती से उठी शब्दों की आवाज़ को मिला सबसे बड़ा सम्मान

विनोद कुमार शुक्ल को 59 वाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार

"मैंने जीवन में बहुत पास से देखा है- पेड़ कैसे खड़े रहते हैं और धूप कैसे उनके साथ चलती है।"

यह पंक्तियाँ किसी दार्शनिक की नहीं बल्कि एक ऐसे कवि की हैं जिन्होंने रोजमर्रा के जीवन में कविता की साँसें खोजीं। विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें इस वर्ष भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाज़ा जा रहा है। यह सम्मान केवल एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि एक संवेदना को, एक दृष्टि को और शब्दों की उस ताकत को दिया जा रहा है जो समय की धूल में छिपी सच्चाइयों को भी उजागर कर देती है।

वरिष्ठ साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 को राजनांदगाँव, छत्तीसगढ़ में हुआ, हिन्दी साहित्य की उन दुर्लभ आवाज़ों में से हैं जो शोर नहीं करतीं पर पाठकों के मन में गूँजती रहती हैं। उन्होंने कृषि विषय से स्नातक किया, पर खेतों के साथ-साथ शब्दों को भी जोता। उनके साहित्य में साधारणता असाधारण बन जाती है। जैसे- गाँव, पेड़, हवा, बच्चे, चुप्पी और इंतज़ार...ये सब उनके पात्र हैं।

वे मुख्य रूप से कवि हैं पर उपन्यास और कहानियों में भी उन्होंने गहरी छाप छोड़ी। उनके लेखन में गद्य और पद्य का एक अद्भुत मिलन दिखता है। वे पाठक को हड़बड़ी से बाहर लाकर सोचने का मौका देते हैं वो भी ठहराव की भाषा में। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान है अब इस मितभाषी लेकिन गूढ़ विचारों वाले लेखक को मिलने जा रहा है। यह केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की मिट्टी का, उसकी भाषा और उसकी संवेदनशीलता का सम्मान है।

सीएम ने घर जाकर दी बधाई

राजनांदगाँव की मिट्टी, वहाँ की बोली, वहाँ की प्रकृति, उनका मन आदि जैसे शब्द सब विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में बार-बार लौटते हैं। उनके लिए छत्तीसगढ़ कोई भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है, जो उनकी कल्पनाओं और विचारों को जन्म देता है।

उन्होंने कभी कहा था, "छत्तीसगढ़ मेरे लिए भाषा नहीं, सोचने का तरीका है।" यही कारण है कि उनकी रचनाओं में प्रकृति, स्थानीयता और मानवीय गहराई इतनी सहजता से मौजूद रहती है।

रायपुर स्थित उनके 'शब्दों से भरे घर' में आज भी साहित्य प्रेमियों का आना-जाना लगा रहता है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी और कहा, "विनोद कुमार शुक्ल ने छत्तीसगढ़ को भारतीय साहित्य की आत्मा में शामिल होने का अवसर दिया है। यह पुरस्कार न केवल उनकी कृतियों को मिला है, बल्कि पूरे प्रदेश की साहित्यिक चेतना को नमन है।"

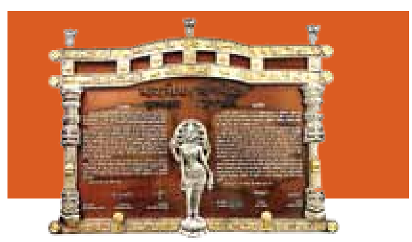

क्यों विशेष है यह सम्मान

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार हिन्दी साहित्य की विश्वसनीयता का प्रतीक है। यह केवल एक लेखक को नहीं, बल्कि उस विचारधारा को मिलता है जो साहित्य को जीवन के सबसे करीब लाती है। विनोद कुमार शुक्ल को यह सम्मान मिलना छत्तीसगढ़ और हिन्दी साहित्य दोनों के लिए गर्व की बात है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि संवेदना की भाषा में लिखा गया साहित्य कभी पुराना नहीं होता – वह समय से परे होता है।

साहित्यिक यात्राः सादगी में गहराई

उनकी कविता संग्रह जैसे *"सब कुछ होना बचा रहेगा"*, *"आकाश धरती को खट-खटाता है"*, *"कभी के बाद अभी"*, *"लगभग जयहिंद-वर्ष 1971"*, और उपन्यास *"नौकर की कमीज"*, *"खिलेगा तो देखेंगे-वर्ष 1996"*, *"दीवार में एक खिड़की रहती थी-वर्ष 1997"* आदि भारतीय साहित्य में अनूठा स्थान रखती हैं। वे कविता को मात्र भाषा का नहीं, बल्कि संवेदना का माध्यम मानते हैं।

उनकी कविता *"हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़"* हो या *"नौकर की कमीज"* जैसे उपन्यास- हर रचना समाज के सतह के नीचे दबे हुए प्रश्नों को उठाती है, पर किसी उद्घोषणा की शैली में नहीं, बल्कि सादेपन और मौन के माध्यम से।

"नौकर की कमीज" पर 1999 में मराठी निर्देशक मणि कौल ने फिल्म बनाई, जो उनके यथार्थ की सादगी और कलात्मक गहराई को परदे पर उतारने का प्रयास था।

उनकी कविता की कुछ पंक्तियाँ

अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ
कि मैं किसी भी भाषा का
अपमान नहीं करूँगा
और मेरी मातृभाषा
हर जन्म में बदलती रहे
इसके लिए मैं बार-बार
जन्म लेता रहूँ-
यह मैं जीव-जगत से कहता हूँ
चिड़ियों, पशुओं, कीट-पतंगों से भी।

विनम्रता में गूँजते शब्द

विनोद कुमार शुक्ल ने न केवल कवि, बल्कि एक अन्वेषक कथाकार और उपन्यासकार के रूप में भी साहित्य को समृद्ध किया। छत्तीसगढ़ के खेत-खलिहान, कस्बाई जीवन और मानवीय अंतर्द्वंद्व उनकी रचनाओं में इतने सहज रूप में आते हैं कि पाठक उन्हें पढ़ते नहीं, बल्कि जीते हैं।

अंतरराष्ट्रीय पहचान और समकालीन योगदान

पिछले वर्षों में उनकी रचनाएँ न केवल हिंदी भाषी पाठकों, बल्कि अंग्रेज़ी, मराठी, तेलुगू और अन्य भाषाओं में भी अनूदित हुई हैं। PEN नाबोकोव पुरस्कार (2023) से सम्मानित शुक्ल की साहित्यिक यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में दर्ज होने जा रही है।

साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार को जानें

साहित्य अकादमी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को यह पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। सन् 1955 से प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में 1लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के आठवीं अनुसूची में बताई गई 22 भाषाओं में से किसी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार को इसे देने की शुरुआत सन् 1965 में हुई जिसमें 11लाख रुपए की धनराशि के साथ प्रशस्तिपत्र और वाग्देवी की काँस्य प्रतिमा भी दी जाती है।

चर्चित कृतियाँ और कुछ अंश

उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में *"दीवार में एक खिड़की रहती थी"*, *"नौकर की कमीज़"*, *"क्योंकि जीवन झरना है"*, *"साहित्य का अस्तित्व"*, और *"लगभग जयहिन्द"* शामिल हैं।

उनकी काव्यात्मक शैली का अंदाज़ा इस अंश से लगाया जा सकता है:

"मैं पेड़ की तरह चुप था पर मेरी हर पत्ती हवा से बात कर रही थी।"

या फिर-

"कमीज़ थी, वह नौकर की थी
पर पहनने पर लगती थी जैसे कोई
और आत्मा भीतर आ गई हो।"

दुनिया ने देखी बस्तर की अद्भुत कला, संस्कृति-परंपरा

बस्तरिया खानपान, शिल्पकला, लोकगीत व लोकनृत्य समेत सात जनजातीय विधाओं को मिला मंच

5 मार्च से 12 अप्रैल तक

- **01** हजार 885 ग्राम पंचायत
- **47** हजार कलाकार
- **12** नगर पंचायत
- **₹5** करोड़ का बजट
- **32** जनपद पंचायत
- **07** विधाओं में प्रतियोगिताएँ

| जनमन रिपोर्ट |

बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा को मंच प्रदान करने के लिए पहली बार बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया। बस्तर संभाग के सभी जिलों में 12 मार्च से जनपद स्तरीय, जिला स्तरीय और अंत में दंतेवाड़ा में 3 से 5 अप्रैल को संभाग स्तरीय रंगारंग आयोजन संपन्न हुआ जिसमें हजारों लोगों ने सहभागिता दी। प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने बस्तर के राम की कथा सुनाई। समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह पधारे। इस आयोजन के माध्यम से बस्तर के आदिवासियों की अनूठी संस्कृति और विलक्षण प्रतिभा ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बस्तर पंडुम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकाड्‌र्स में भी स्थान मिला है।

बस्तर की कला, संस्कृति, परंपरा को पूरे विश्व तक पहुँचाने का काम कर रही मोदी सरकार: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम के समापन समारोह में शिरकत करने के लिए 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा पहुँचे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर अमित शाह ने बस्तर महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जल-जंगल, जमीन और संस्कृति के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनकी लोकप्रियता उस समय की सरकार को सहन नहीं हुई और साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी गई। आज जब पूरा बस्तर लाल आतंक से मुक्त होने की कगार पर है, विकास की राह पर चल पड़ा है, तो प्रवीर चंद्र जी की आत्मा जहाँ भी होगी बस्तरवासियों को आशीर्वाद दे रही होगी। शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अगले साल से बस्तर पंडुम में देशभर के आदिवासी कलाकारों को शामिल किया जाएगा। इस वर्ष इस आयोजन में सात विधाओं को शामिल किया गया है, अगले साल से इसमें 12 विधाओं में प्रतियोगिता होगी। उन्होंने कहा कि बस्तर पंडुम को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाने के लिए सभी देशों के राजदूतों को बस्तर भ्रमण करवाकर यहाँ की परंपरा, संस्कृति और कला को पूरे विश्व तक पहुँचाने का काम मोदी सरकार कर रही है। यह पंडुम स्थानीय और पारंपरिक कला, संस्कृति, शिल्पकला, तीज-त्यौहार, खानपान, बोली, भाषा, रीति-रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, पारंपरिक गीत संगीत तथा व्यंजन को मूल रुप से सवंर्धित और संरक्षित

करने का काम करेगा। शाह ने कहा कि बस्तर का युवा आधुनिक शिक्षा प्राप्त करे, विश्व के युवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करे, दुनियाभर की समृद्धि प्राप्त करे, लेकिन अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराओं को कभी न भूले। बस्तर की संस्कृति, बोलियाँ, वाद्ययंत्र, भोजन छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत की संस्कृति का गहना है। हमें इसे संजोकर रखना है। उन्होंने कहा कि वह जमाना गया जब यहाँ गालियाँ चलती थीं और बम धमाके होते थे। नक्सली हथियार डालकर मुख्यधारा में आ जाएँ क्योंकि बस्तर विकास चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी बस्तर को सबकुछ देना चाहते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब बस्तर में शांति हो। यहाँ के बच्चे स्कूल जाएँ, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, हर गाँव में दवाखाना हो, तहसील में अस्पताल हो तभी विकास संभव है। यह तभी संभव होगा जब बस्तर के लोग तय करें कि वे हर गाँव को नक्सलमुक्त बनाएँगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषणा की है कि जो जो गाँव सभी नक्सलियों को सरेंडर कराएगा उस गाँव को नक्सलमुक्त घोषित कर एक करोड़ रुपये की विकास राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। हर जिले के एक विशिष्ट उत्पाद को जीआई टैग से जोड़कर देशभर के बाजारों में उसके मार्केटिंग की व्यवस्था की है। शाह ने कहा कि नक्सली हथियार लेकर बस्तर का विकास नहीं रोक सकते। बस्तर अब भय नहीं बल्कि भविष्य का पर्याय बन चुका है। जहाँ कभी गोलियों की गूँज थी वहाँ अब मशीनों की आवाज आती है। जहाँ गाँव वीरान थे वहाँ स्कूलों की घंटियाँ सुनाई देती हैं। जहाँ सड़कें स्वप्न थीं वहाँ राजमार्ग बन रहे हैं। विकास, विश्वास और विजय की लौ के साथ बस्तर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि विकास तब होगा जब सुकमा से कोई सब इंस्पेक्टर बने, बस्तर से बैरिस्टर, दंतेवाड़ा से डॉक्टर और कांकेर से कलेक्टर बनें। ऐसे ही बस्तर का विकास और निर्माण हमें करना है।

मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगा नक्सलवाद

शाह ने कहा कि मोदी सरकार मार्च 2026 तक पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के प्रति कटिबद्ध है। जो लोग यह समझ गए हैं कि विकास के लिए हाथ में बंदूक नहीं कम्प्यूटर चाहिए, आईईडी और हथगोला नहीं बल्कि कलम चाहिए, उन सबने सरेंडर कर दिया है। इस साल अब तक 521 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2024 में 881 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। जो हिंसा के रास्ते पर चलेंगे उनसे सुरक्षाबल सख्ती से निपटेंगे।

नक्सलवाद के खात्मे साथ लौटेंगे बस्तर के सुनहरे दिन: मुख्यमंत्री साय

बस्तर पंडुम उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर अब बदल रहा है और यह बदलाव स्थायी होगा। बस्तर के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजन इसी जनभावना के प्रतीक हैं। साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया है। माँ दंतेश्वरी की कृपा से यह संकल्प अवश्य पूरा होगा। उन्होंने कहा कि बस्तर एक प्राकृतिक स्वर्ग है। यहाँ अनेक जलप्रपात और अबूझमाड़ के घने जंगल हैं। यहाँ फिर से देश-दुनिया के पर्यटक आएँगे और बस्तर को उसका गौरवमय स्थान मिलेगा। बस्तर पंडुम में 47 हजार कलाकारों और बस्तर ओलंपिक में 1 लाख 65 हजार युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन की सबसे बड़ी गवाही है। साय ने कहा कि पिछले 15 महीनों से राज्य में डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों से जुड़ी योजनाएँ, 70 लाख माताओं और बहनों को हर महीने 1000 रुपये देने वाली महतारी वंदन जैसी योजनाओं के माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा किया जा रहा

है। पीएम जनमन योजना के माध्यम से अबूझमाड़िया, कोरवा, बिरहोर, पंडो जैसी विशेष जनजातियों तक सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 6500 जनजातीय गाँवों में सर्वांगीण विकास होगा। यह योजना ग्रामीण समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल इलाकों में नियद नेल्ला नार योजना से विकास हो रहा है। 100 से अधिक गाँवों में सुरक्षा कैंप खोले गए हैं। इन कैंपों के माध्यम से सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएँ पहुँचाई जा रही हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होगा और विकसित, खुशहाल राज्य के रुप में प्रतिष्ठित होगा। हर घर में खुशहाली और समृद्धि आएगी।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केवल दिल्ली से नीतियाँ नहीं बनाते, वे बस्तर की पीड़ा को महसूस करने के लिए स्वयं यहाँ आते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं, उनके साथ भोजन करते हैं। यह बस्तर के प्रति सच्ची संवेदना और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री साय पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रुप में बस्तर की मिट्टी से जुड़े हुए हैं।

बस्तर पंडुम यानी बस्तर का उत्सव

बस्तर पंडुम गोंडी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बस्तर का उत्सव। इस आयोजन में जनजातीय नृत्यों के तहत गेड़ी, गौर माड़िया, ककसाड़, मांदरी, हुलकीपाटा, परब आदि का प्रदर्शन किया गया। जनजातीय गीत चैतपरब, जगारगीत, धनकुल, लेजा, हुलकीपाटा, जनजातीय नाट्य श्रेणी में भतरा नाट, जनजातीय वाद्ययंत्रों में धनकुल, ढोल, चिटकुल, तोड़ी, अकुंम, झाब, मांदर, मृदंग, बिरिया ढोल, सारंगी, गुदुम, मोहरी, सुलुड, मुंडाबाजा, चिकारा शामिल रहे। जनजातीय वेशभूषा एवं आभूषण में लुरकी, करधन, सुतिया, पैरी, बाहूँटा, बिछिया, ऐंठी, बंन्धा, फुल्ली, धमेल, नाँगमोरी, खोचनी, मुंदरी, सुर्रा, सुता, पटा, पुतरी, नकबेसर आदि आभूषणों का प्रदर्शन किया गया। जनजातीय चित्रकला एवं शिल्पकला श्रेणी में घड़वा, माटी कला, काष्ठ, ढोकरा, लौह प्रस्तर, गोदना, भित्तिचित्र, शीशल, कौड़ी शिल्प, बाँस की कंघी, गीकी, घास के दानों की माला आदि ने दर्शकों को अभिभूत किया। जनजातीय पेय पदार्थ और व्यंजन में सल्फी, ताड़ी, छिंदरस, लाँदा, कोसरा, जोन्धरा व माड़िया पेज, चापड़ा चटनी, सुक्सी पुड़गा, मछरी पुड़गा, मछरी झोर, आमट साग, तिखुर, बोबो आदि बनाने की विधि, स्थानीय मसाले, स्वाद, का प्रस्तुतिकरण बस्तर पंडुम का आकर्षण रहा। आयोजन में समाज प्रमुखों व गणमान्यजनों ने विभिन्न आयामों के आधार पर प्रतिभागियों को अंक दिए। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 12 मार्च को विधानसभा में बस्तर पंडुम के लोगो का अनावरण किया था। बस्तर पंडुम के लोगो में इंद्रावती नदी, चित्रकोट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वनभैंसा, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, बायसन हॉर्न, कुकुंट, तुरही, ढोल, सल्फी और ताड़ी के पेड़ को शामिल किया गया है।

दंतेवाड़ा में जनजातीय संस्कृति का समागम

45 दिन तक चले बस्तर पंडुम का संभाग स्तरीय आयोजन 3 से 5 अप्रैल तक दंतेवाड़ा में किया गया। उप मुख्यमंत्री तथा प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा तथा वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने समापन समारोह का उद्घाटन किया। तीन दिवसीय समापन समारोह में कवि कुमार विश्वास ने बस्तर के राम कथा भी सुनाई। दंतेवाड़ा के हाईस्कूल मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम देश विदेश में बस्तर की अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ पूरी बस्तरिया संस्कृति एक पंडाल के नीचे समाहित हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर की गौरवशाली संस्कृति को सहेजने, सँवारने और इसे वैश्विक पटल पर पहुँचाने के लिए सरकार ने बस्तर पंडुम कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ मेरा जन्म न होने से मैं यहाँ की संस्कृति और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन से वंचित रहा हूँ किंतु आज इस कार्यक्रम में सभी स्वाद का अनुभव करने का अवसर मिला। वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि हमारे बस्तर क्षेत्र में जन्म से मृत्यु तक पंडुम मनाते हैं। इस समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संदेश देने में हमारी परंपरा, रीति रिवाज की अहम भूमिका है। दोनों मंत्रियों ने प्रदर्शनी में लगे जनजातीय कला स्टॉल का अवलोकन किया। जनजातीय संस्कृति के वाद्य यंत्रों का वादन किया और जनजातीय व्यंजनों का स्वाद लेकर उनकी सराहना की। आयोजन में सभी प्रशासनिक अधिकारी तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिगण के साथ ही समाज के गणमान्यजन मौजूद थे।

यहाँ भगवान राम के कदम पड़े थे इसलिए नंगे पांव चलने पर भी कांटे नहीं चुभतेः कुमार विश्वास

संभाग स्तरीय समापन समारोह में दंतेवाड़ा पहुँचे कवि कुमार विश्वास ने भगवान राम पर आख्यान प्रस्तुत करते हुए कहा कि बस्तर आना मेरा सौभाग्य है। भगवान राम के कदम इस क्षेत्र में पड़े थे इसलिए यहाँ नंगे

पांव चलने पर भी काँटे नहीं चुभते हैं। दंडकारण्य यानी बस्तर के कण-कण में राम विराजे हैं। देश ने आज कहा है कि राम आएँगे लेकिन बस्तर के लोग सदियों से कह रहे-इंजरम, अर्थात राम आए हैं। यहाँ के लोगों का राम से सीधा नाता है। अयोध्या में राम राजकुमार थे, बस्तर में संघर्षशील रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बने। भगवान राम ने देश में दो ही शिवलिंग स्थापित किए थे। एक रामेश्वरम में है और दूसरा सुकमा के रामाराम में। विश्वास ने कहा कि ढोलकल में विराजे गणेश जी की कथा अद्भुत है। गीदम का नाम गिद्धराज जटायु के आधार पर हुआ। उन्होंने कहा कि वाम पथ पर जाते लोग राम पथ पर लौट आएँ यही कामना माँ दंतेश्वरी से करता हूं। सीता की रसोई छत्तीसगढ़ के मैनपाट में है। विश्व में भोजन की कमी हो सकती है लेकिन बस्तर में नहीं। यहाँ माता जगदम्बा ने रसोई बनाई थी। राम को देखने के लिए दृष्टि होनी चाहिए। इसी दंडकारण्य में दो महिलाओं ने राम को देखा। जिस एक ने राम को देखा वह सूर्पनखा आज भी अपमानित है। दूसरी ने भाव की घनीभूत भावना से देखा जिसे राम ने माता कौशल्या के बाद अपनी माँ के रुप में देखा वह इसी छत्तीसगढ़ से शबरी माँ थीं। आयुर्वेद में जिस बेर को अपथ्य माना गया है उसी से राम तृप्त हुए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर प्रगति की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद की स्थिति पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रमुख सचिव, आईबी, सीआरपीएफ, एनआईए, बीएसएफ, आईटीबीपी के महानिदेशक और छत्तीसगढ़ के डीजीपी सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के समूल नाश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। 31 मार्च से पहले ही छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में नक्सलवाद एक इतिहास बन जाएगा। नक्सलवाद के कारण कई पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई हैं। नक्सलवाद फिर से जड़ न जमा पाए इसलिए इसका समूल नाश आवश्यक है। नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में बिखराव नहीं होने देना है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर संतोषजनक प्रगति हुई है। उन्होंने नक्सल प्रभावित इलाकों में जन-जन तक सरकारी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए बनाई गई नियद नेल्ला नार का दायरा कैंप से 5 किलोमीटर से बढ़ाकर 10 किलोमीटर करने को कहा। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियान का मोमेंटम किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिए। इससे पहले अमित शाह ने दंतेवाड़ा में सुरक्षा बल के जवानों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने नक्सल मोर्चे पर घायल जवानों के बेहतर उपचार के लिए रायपुर और जगदलपुर में विशेष अस्पतालों की स्थापना की घोषणा भी की। जवानों से कहा कि सरकार हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी है।

लास्ट पंच

अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस

हम सभी अपनी जीवनशैली में बदलाव कर पृथ्वी को हरा-भरा बनाते हुए उसकी गुणवत्ता और उर्वरता को बनाए रखने का संकल्प लें। आइए, हम सभी अपने प्रयासों से पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं रखने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें।

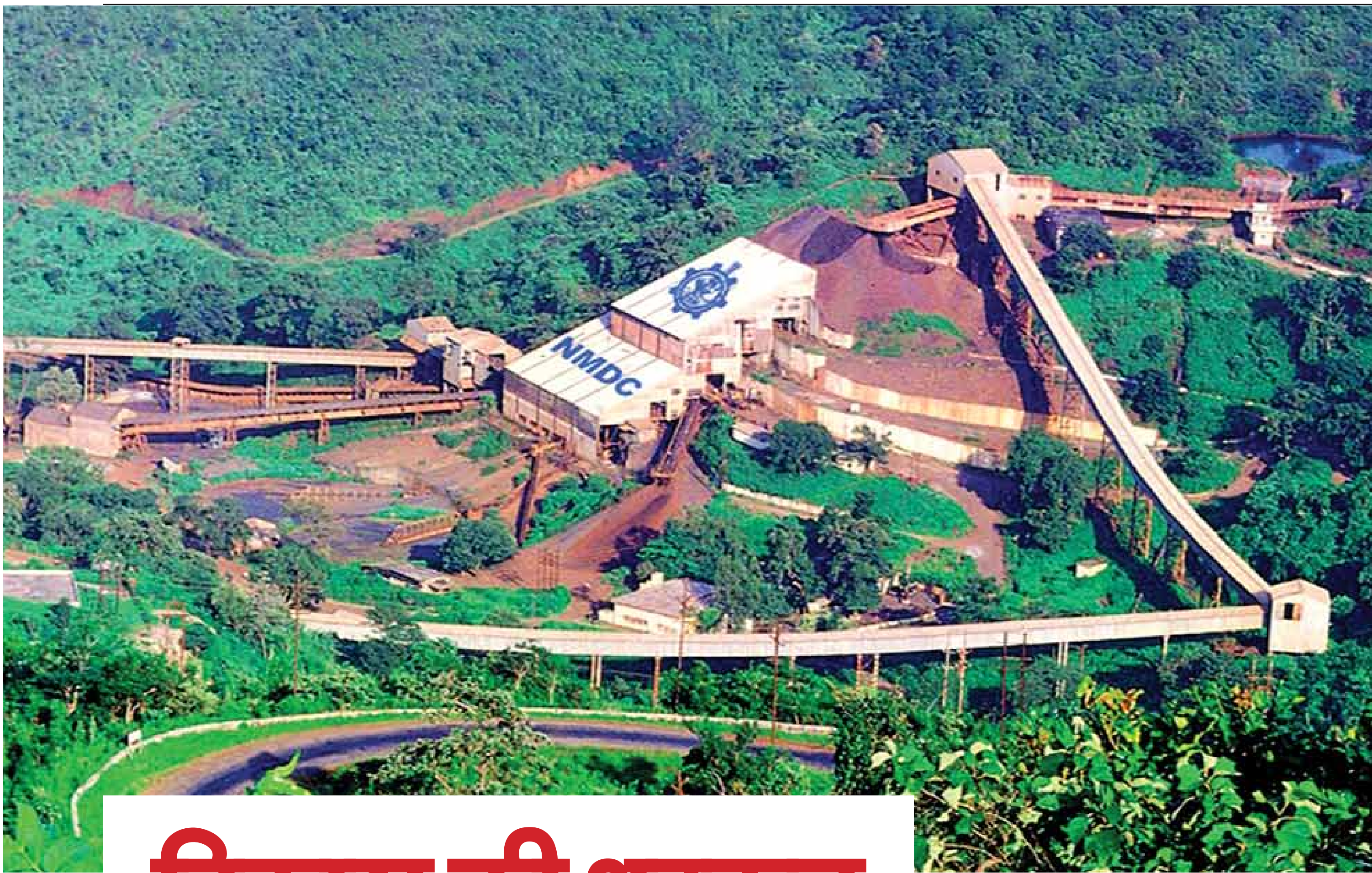

विकास की धड़कन पूरे लय से धड़क रहा देश का मिनरल हार्ट

अब तक 44 मिनरल ब्लॉकों की सफल नीलामी, कटघोरा में खुलने वाली पहली लीथियम खदान

बैलाडीला क्षेत्र में तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी, प्रक्रिया जारी

। जनमन रिपोर्ट ।

देश का मिनरल हार्ट छत्तीसगढ़ अपनी लय पकड़ चुका है। खनिज व खनन के क्षेत्र में पर्यावरण संतुलन व संरक्षण पर विशेष फोकस करते हुए प्रदेश सरकार के नवाचार ने जहाँ एक ओर इसे आधुनिक गति दी है तो दूसरी ओर इससे प्राप्त राजस्व का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक विकास के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम पारदर्शी खनन नीति, ई-नीलामी, डिजिटल निगरानी और पर्यावरण-संवेदनशील खनन रणनीतियों को अपनाना है। इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ के खनिज राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्व की तुलना वर्तमान के हालात से करें तो खनिज राजस्व में 30 गुना वृद्धि हुई है, जो 2023-24 में 13,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और 2024-25 में अप्रैल से फरवरी तक ही 11,581 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया जा चुका है।

भारत सरकार द्वारा देश के आर्थिक एवं सामरिक विकास को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के लिए राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन की घोषणा जनवरी, 2025 में की गई है। इसके अनुरूप प्रदेश में खनिज विभाग द्वारा वर्ष 2024-25 से ही क्रिटिकल एवं सामरिक महत्व के खनिजों के अन्वेषण व खोज पर विशेष ध्यान दिया गया है।

वर्तमान में 44 खनिज ब्लॉकों की सफल ई-नीलामी की जा चुकी है इसमें से 10 ब्लॉक क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स हैं, यानी क्रिटिकल व सामरिक महत्व के खदान। वर्तमान में इन खनिजों के अन्वेषण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत 56 अन्वेषण परियोजनाओं में से 31 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स पर आधारित हैं।

प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश के समृद्ध राज्यों में से एक है। इसलिए इसे देश का मिनरल हार्ट कहा जाता है। कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर, बॉक्साइट, स्वर्ण, निकल, क्रोमियम और प्लेटिनम समूह के तत्व सहित कुल 28 प्रकार के खनिजों की उपलब्धता ने छत्तीसगढ़ को खनिज संपन्न राज्य के साथ देश के मानचित्र पर एक विशेष जगह प्रदान की है।

पर्यावरणीय संतुलन, पारदर्शी तरीका व वैज्ञानिक रूप से खदानों के संचालन के लिए सरकार ने कई नई पहल की हैं। सेटेलाइट इमेजरी और माइनिंग सर्विलियेंस सिस्टम का उपयोग किया रहा है। गौण खनिज खदानों में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक पद्धति से खनन को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है। बेहतर कार्य करने वाले पट्टेधारियों को 'स्टार रेटिंग' प्रणाली के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इन खनिज ब्लॉकों में हुई नीलामी

चूना पत्थर	14	निकल, क्रोमियम	2
लौह अयस्क	9	ग्रेफाइट	2
बॉक्साइट	11	ग्लूकोनाइट	2
स्वर्ण	3	लीथियम	1

देश का पहला लीथियम ब्लॉक

कोरबा जिले के कटघोरा में देश में पहली बार खनिज लीथियम ब्लॉक की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस नीलामी के तहत इस ब्लॉक को मेसर्स साउथ मायकी मायनिंग कंपनी को 76 प्रतिशत प्रीमियम राशि पर आवंटित किया गया है। राज्य के सुकमा एवं कोरबा जिले में भी लीथियम अन्वेषण कार्य किया जा रहा है जिसमें लीथियम के भण्डार पाये जाने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा प्रदेश में अब तक 10 क्रिटिकल एवं डीप सीटेड मिनरल्स ब्लॉक्स की नीलामी की गई है।

बैलाडीलाः तीन नए ब्लॉक

बैलाडीला क्षेत्र भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क भंडारों में से एक है। यहाँ तीन नए लौह अयस्क ब्लॉकों की ई-नीलामी प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा कांकेर जिले के हाहालद्दी लौह अयस्क खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है।

सामाजिक विकास व बुनियादी सुविधाओं में निवेश

खनिज राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्रदेश के सामाजिक विकास में निवेश किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 1,673 करोड़ रुपये की निधि प्राप्त हुई है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल और कौशल विकास सहित 9,362 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। इससे खनन प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हो रहा है।

लगातार जारी है खनिजों की खोज

राज्य सरकार ने चूना पत्थर, बॉक्साइट, लौह अयस्क और ग्रेफाइट सहित कुल 13 खनिज परियोजनाओं में अन्वेषण कार्य शुरू किया है। प्रारंभिक सर्वेक्षणों में चूना पत्थर के 283 मिलियन टन, लौह अयस्क के 67 मिलियन टन और बॉक्साइट के 3 लाख टन भंडार का अनुमान लगाया गया है। स्वर्ण, ग्रेफाइट और ग्लूकोनाइट जैसे खनिजों की खोज भी की जा रही है, जिससे राज्य के खनन क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। इसके अलावा, सूरजपुर जिले के जाजावल क्षेत्र में यूरेनियम ब्लॉक के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। कोल बेड मीथेन पूर्ववर्ती कोरिया जिले में वेदांता लिमिटेड एवं ऑईलमैक्स को पेट्रोलियम अन्वेषण लायसेंस स्वीकृत किया गया है। मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड (मोईल) द्वारा सीएमडीसी के साथ प्रदेश में प्रथम बार बलरामपुर क्षेत्र में खनिज मैगनीज का भंडार चिन्हित किया गया है।

ट्रस्ट के गठन की तैयारी

खनिज संपदा से परिपूर्ण छत्तीसगढ़ भारत के अग्रणी औद्योगिक और आर्थिक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यहाँ से प्राप्त खनिज प्रदेश को न केवल आर्थिक मजबूती प्रदान कर रहे हैं, बल्कि प्रदेश अपने खनन नीतियों के कारण हरित और सतत विकास की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। इसका प्रमाण यह भी है कि मुख्य खनिजों के अन्वेषण के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की है। इसी तर्ज पर प्रदेश सरकार के खनिज विभाग द्वारा राज्य के गौण खनिजों के व्यवस्थित विकास एवं अन्वेषण के लिए राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट की स्थापना की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का परिणाम आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ भारत के माइनिंग हब के रूप में सुनिश्चित करेगा।

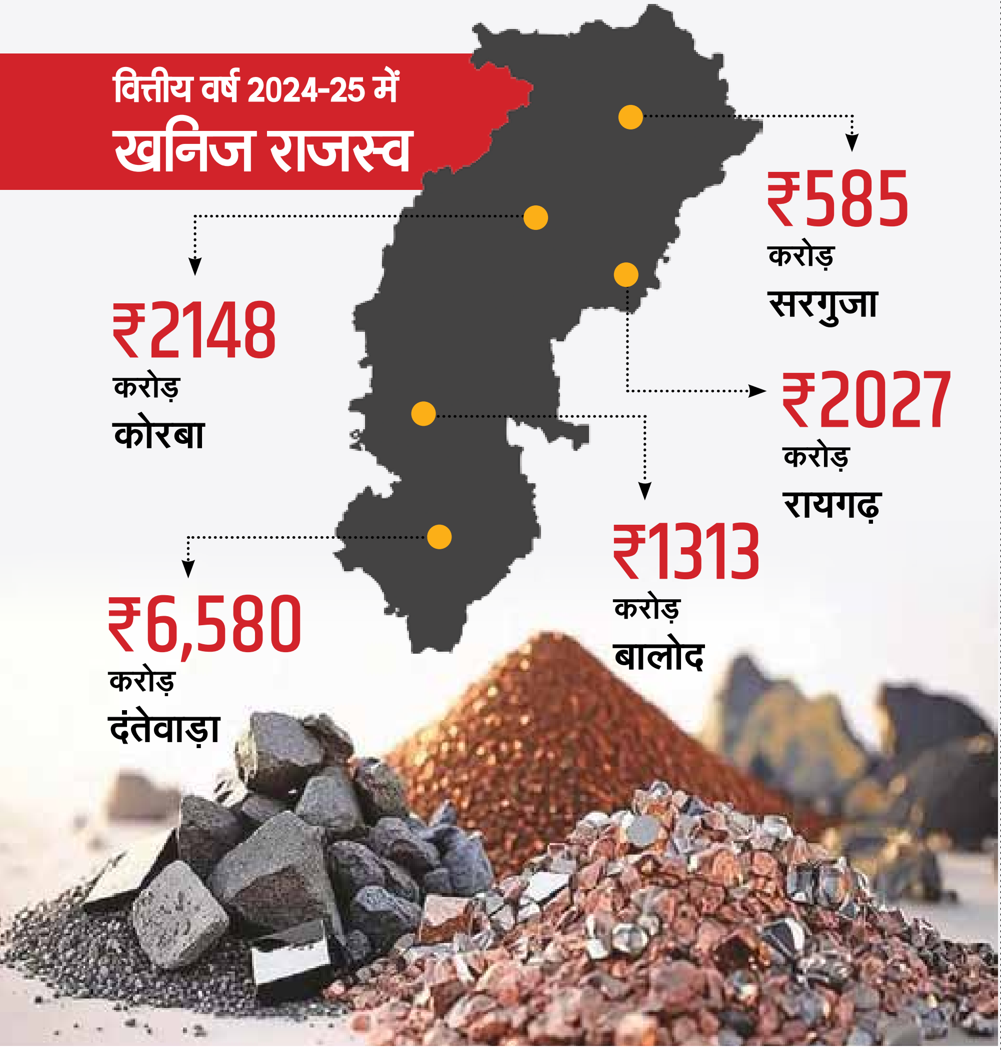

क्षमता और अवसंरचना

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 16 प्रतिशत से अधिक प्रदान करता है। बस्तर क्षेत्र में स्थित बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना जैसी उन्नत खानों से हर साल 11 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ टिन सांद्रण उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है और यह देश के कुल टिन भंडार का 35.4 प्रतिशत योगदान करता है।

तकनीक का प्रयोग और माइनिंग फ्यूचर

खनिज ब्लॉकों के आवंटन के लिए राज्य की विष्णु देव साय की सरकार ने ई-नीलामी प्रणाली को अपनाया है, जिससे पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हुई है। यह दृष्टिकोण न केवल राजस्व बढ़ा रहा है बल्कि हरित ऊर्जा और हाई-टेक उद्योगों के लिए आवश्यक खनिजों में निवेश को आकर्षित कर रहा है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ का ध्यान महत्वपूर्ण खनिजों पर केंद्रित है, जो भारत के राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के साथ मेल खाता है। यह राज्य आयात पर निर्भरता कम करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रहा है। साथ ही, रेल गलियारे जैसे बुनियादी ढाँचे में निवेश किया जा रहा है ताकि खनिज परिवहन को बढ़ावा दिया जा सके।

सरकार की नीतियाँ व नवाचार दे रहे लाभ

- छत्तीसगढ़ में प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार की ओर से खनन क्षेत्र में किए जा रहे नवाचार व दूरदर्शी नीतियों के कारण खनिज और खनन गतिविधियाँ न केवल प्रदेश के आर्थिक विकास में बल्कि सामाजिक प्रगति में भी व्यापक योगदान दे रही हैं।
- **आर्थिक लाभः** खनन से राज्य को बड़ी मात्रा में राजस्व मिलता है, जिसका उपयोग बुनियादी ढाँचे, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं में किया जा रहा है। 2024-25 के वित्तीय वर्ष में, राज्य ने 14,195 करोड़ का खनिज राजस्व प्राप्त किया, जो पिछले वर्ष से 11 प्रतिशत अधिक है। खनन क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से खदानों में और अप्रत्यक्ष रूप से खनिज-आधारित उद्योगों में रोजगार उत्पन्न करता है। यहाँ से निकले खनिज प्रदेश ही नहीं देश के औद्योगिक विकास को गति देते हैं।
- **मजबूत हो रही स्थितिः** खनन और खनिज न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। लीथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण से आयात पर निर्भरता कम होगी जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी। आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पर्यावरणीय प्रभाव कम करने और जिम्मेदार खनन सुनिश्चित करने के प्रयास सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में खनन से न केवल आर्थिक प्रगति होती है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की समग्र विकास यात्रा को भी मजबूती देता है।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल

केंद्र सरकार ने कांगेर घाटी को स्थाई सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा

| जनमन रिपोर्ट |

बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज अस्थाई सूची में शामिल किया गया है। इस वर्ष 7 मार्च को यूनेस्को ने इसकी घोषणा की। इसके साथ ही अपनी अनूठी जैव विविधता के लिए मशहूर यह नेशनल पार्क भारत का नया यूनेस्को धरोहर का दावेदार बन गया है। यह छत्तीसगढ़ पर्यटन के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में बताया कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को स्थाई विश्व धरोहर का दर्जा देने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा गया है। आने वाले वर्षों में इसे स्थाई विश्व धरोहर का दर्जा भी मिल सकता है। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार दिसंबर 2023 में छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वैश्विक पहचान दिलाने की योजना बनाई थी। विशेषज्ञों ने इस उद्यान की जैव विविधता, पुरातात्विक धरोहर और अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र का गहराई से अध्ययन किया और इसे यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। यह पहली बार है कि छत्तीसगढ़ का कोई स्थल इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुआ है। सरकार का प्रयास है कि इसे यूनेस्को की स्थाई विश्व धरोहर सूची में शामिल कराया जाए।

कांगेर घाटी में है जादुई आकर्षण

कांगेर घाटी नेशनल पार्क एक जंगल भर नहीं है, यह एक रहस्यमयी संसार है जो पर्यटकों को जादुई आकर्षण से अपनी ओर खींचता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान का नाम इस जंगल से गुजरने वाली कांगेर नदी के नाम पर पड़ा है। कांगेर नदी राष्ट्रीय उद्यान की लंबाई में बहती है। यह नेशनल पार्क करीब 200 वर्ग किमी में विस्तृत है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। यहाँ साल, सागौन, बाँस आदि आर्द्र पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। उद्यान क्षेत्र में पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनमें पहाड़ी मैना (ग्रेकुला रिलिजियोसा पेनिनसुलारिस) सबसे लोकप्रिय है। पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है। यह मनुष्यों की आवाज की हूबहू नकल करने के लिए प्रसिद्ध है। कांगेर घाटी का पर्यावास प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के अनुकूल है। कांगेर घाटी के रहस्यमय संसार में 15 भूगर्भीय गुफाओं की खोज की गई है जो बाहरी दुनिया के लिए आश्चर्यजनक हैं। इनमें से कोटमसर, कैलाश और दंडक गुफा अपनी अद्भुत भूगर्भीय संरचनाओं के लिए पर्यटकों के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। ये गुफाएँ पुरातात्विक कहानियाँ भी समेटे हुए हैं। इन भूगर्भीय संरचनाओं में स्टेलग्माइट्स और स्टैलेक्टाइट्स शामिल हैं। यहाँ ड्रिपस्टोन और फ्लोस्टन के साथ भूमिगत चूना पत्थर की गुफाएँ हैं। स्टेलग्माइट और स्टैलेक्टाइट का निर्माण निरंतर जारी है और यह बढ़ रहा है। इन गुफाओं में जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सबसे लोकप्रिय कोटमसर गुफा 60 से 120 फीट तक गहरी है तथा यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इसकी लंबाई 4500 फीट है। यहाँ चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया से कई प्राकृतिक संरचनाएँ बन गई हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में ही तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है जो दुनियाभर में प्रसिद्ध है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क के पूर्वी भाग में भैंसाधारा जलाशय है जहाँ खूबसूरत रेतीले तट हैं। यहाँ मगरमच्छ की क्रोकोडिलस पोरोसस प्रजाति निवास करती है। उद्यान में ऊदबिलाव, माउस डियर, जाइंट गिलहरी, लेथिस सॉफ्टशेल कछुआ, जंगली भेड़िया जैसे दुर्लभ प्राणी निवास करते हैं। कांगेर घाटी में पक्षियों की 200 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ 900 से अधिक वनस्पति प्रजातियाँ हैं। तितलियों की यहाँ 140 प्रजातियाँ मिलती हैं। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए पर्यटकों को जिप्सी की सफारी उपलब्ध कराई जाती है।

कांगेर घाटी का यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल होना राज्य के लिए गौरव का विषय है। यह उपलब्धि कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता का परिणाम है। इससे पर्यटन और रोजगार की नई संभावनाएँ खुलेंगी। हम भविष्य में भी अपनी धरोहरों के संरक्षण के लिए मिलकर प्रयास करते रहेंगे।

विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विश्व में बनेगी खास पहचान

अधिकारियों ने बताया कि यूनेस्को की अस्थाई सूची एक खास सूची होती है। इसमें दुनियाभर के वह स्थान शामिल किए जाते हैं जिन्हें भविष्य में विश्व धरोहर घोषित किया जा सकता है। यह पहला और सबसे अहम पड़ाव है। कांगेर घाटी ने पहला पड़ाव पार कर लिया है। आगे चलकर यह स्थल यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल होगा तो इसकी पूरे विश्व में खास पहचान होगी। इससे कांगेर घाटी और आसपास के गाँवों को भी फायदा होगा।

देशभर के छह स्थल यूनेस्को की अस्थाई सूची में

तेलंगाना के मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर और मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में बुंदेलों के महल व किले सहित कुल छह स्थलों को इस वर्ष यूनेस्को की अस्थाई सूची में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, मौर्य मार्गों के किनारे अशोक के शिलालेख, चौंसठ योगिनी मंदिर और उत्तर भारत के गुप्तकालीन मंदिर इसमें शामिल हैं। यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार चौंसठ योगिनी मंदिरों में देश के कई स्थानों पर स्थित स्थल शामिल हैं। इन स्थलों के जुड़ने के साथ ही अब भारत के 62 स्थल यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हो गए हैं। ज्ञात हो कि भारत ने 2024 में पहली बार विश्व धरोहर समिति की मेजबानी की थी जिसमें असम के अहोम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली मोइदम को यूनेस्को टैग प्रदान किया गया था।

संस्कारों की धरती, साहित्य की नगरी

यह है राजनांदगाँव

| जनमन रिपोर्ट |

अगर छत्तीसगढ़ की आत्मा को महसूस करना हो तो कदम रखिए राजनांदगाँव की धरती पर। यह सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि संस्कारों की थाती, कला और साहित्य की प्रयोगशाला और धार्मिक आस्था की ऊर्जा से परिपूर्ण एक ऐसा स्थल है जहाँ इतिहास और वर्तमान एक-दूसरे से हाथ मिलाते नजर आते हैं।

इस शहर की नींव केवल ईंट-पत्थर से नहीं, बल्कि गोंड रियासतों की विरासत, मराठा प्रभाव और ब्रिटिश कालीन प्रशासनिक समझ से बनी है। वर्ष 1830 में गोंड राजा मघराज शाह द्वारा स्थापित यह नगर आगे चलकर एक स्वतंत्र रियासत के रूप में उभरा, जिसे 1865 में ब्रिटिश सरकार ने मान्यता दी। यहाँ का राजपरिवार न केवल शासनकर्ता रहा, बल्कि कला, संस्कृति और शिक्षा का संवाहक भी बना। यही वह भूमि है जहाँ आगे चलकर हिंदी साहित्य के पुरोधा गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी कलम से हिंदी कविता को नई दृष्टि दी। राजनांदगाँव की पहचान केवल इतिहास तक सीमित नहीं। यह आज भी अपनी 'संस्कारधानी' की उपाधि को बखूबी निभा रहा है, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, संस्कृति के मंच पर या धार्मिक आस्था की ऊँचाइयों तक।

यह वह शहर है, जिसकी गोद में बसी है माँ बमलेश्वरी की आराधना भूमि डोंगरगढ़, जहाँ हर साल नवरात्रि के दौरान लाखों श्रद्धालु आकर अपनी आस्था को पहाड़ों पर चढ़कर साबित करते हैं। यह वह क्षेत्र है, जहाँ खैरागढ़ विश्वविद्यालय जैसा संस्थान न केवल देश, बल्कि एशिया का पहला संगीत विश्वविद्यालय बनकर कला की साधना को अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुँचाता है। और जब आप इस शहर की गलियों से गुजरेंगे तो न सिर्फ इतिहास की खुशबू आएगी, बल्कि आपको मिलेंगे वो लोग, जिनके बोल-व्यवहार में छत्तीसगढ़ी आत्मा बसती है और जिनके हाथों में हैं लोक कला, हस्तशिल्प और स्वाद के हुनर। राजनांदगाँव की कहानी कोई

बंगाल नागपुर कॉटन मिल

औद्योगिक क्रांति की धड़कन

राजनांदगाँव की धरती पर बंगाल नागपुर कॉटन मिल (BNC मिल) का स्थापना का कार्य इंग्लैंड की मैकबेथ ब्रदर्स द्वारा किया गया था। यह मिल राजनांदगाँव रेलवे स्टेशन के निकट 5 एकड़ भूमि पर स्थापित की गई थी। इसका उद्घाटन जनवरी 1894 में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश सर कॉमर पैथेरम की उपस्थिति में हुआ था। इस मिल ने न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती दी, बल्कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र में श्रमिक आंदोलनों की नींव भी रखी। 1918 से 1940 के बीच, प्रसिद्ध समाजसेवी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में, इस मिल के श्रमिकों ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जो क्षेत्र के श्रमिक आंदोलन का प्रारंभिक बिंदु बना। हालाँकि, समय के साथ, यह मिल बंद हो गई और वर्तमान में इसके अवशेष ही शेष हैं। फिर भी, बंगाल नागपुर कॉटन मिल का योगदान राजनांदगाँव के औद्योगिक और सामाजिक विकास में अविस्मरणीय है।

इतिहास की परतें

जहाँ समय ने रखी संस्कारों की नींव

राजनांदगाँव की भूमि सिर्फ मिट्टी की नहीं, यह स्मृतियों और संस्कारों से बनी है। इसका अतीत उतना ही गूढ़ और गहराई भरा है, जितना किसी पुरातन ग्रंथ का पहला अध्याय। यह क्षेत्र कभी गोंड शासकों की वीरता और मराठों की सूझबूझ का गवाह रहा। 18वीं सदी में जब मराठा साम्राज्य ने यहाँ की कमान संभाली तो इस धरती पर प्रशासन और परंपराओं का एक सुंदर संगम दिखा। फिर आया वह दौर जब ब्रिटिश सत्ता की छाया इस नगर पर पड़ी और यह बन गया एक स्वतंत्र रियासत जहाँ शासक केवल ताजधारी नहीं, बल्कि संस्कृति और शिक्षा के संरक्षक भी थे। इन राजाओं ने केवल किलों और महलों की नींव नहीं रखी, उन्होंने शब्दों, कला और परंपराओं की विरासत भी सहेजी। यही वजह है कि यह शहर आज 'संस्कारधानी' कहलाने में गर्व महसूस करता है।

काल्पनिक आख्यान नहीं, बल्कि वास्तविकता के गर्भ से निकली एक जीवंत गाथा है जो हमें बताती है कि कैसे एक नगर, अपने अतीत को संजोकर, वर्तमान को सजाकर, भविष्य की ओर बढ़ सकता है, गरिमा और गौरव के साथ। नाम की बात करें तो नंदगाँव मराठा रियासत का हिस्सा था, जो बाद में ब्रिटिश शासनकाल में विकसित होकर राजनांदगाँव रियासत बना। सन् 1948 में, रियासत राज्य और राजधानी शहर राजनांदगाँव मध्य भारत के बाद में मध्य प्रदेश के दुर्ग जिले में विलय कर दिया गया था। 26 जनवरी 1973 में, राजनांदगाँव को दुर्ग जिले से बाहर निकाला गया और नया राजनांदगाँव जिला बनाया गया था। सन् 1998 में, राजनांदगाँव जिले के कुछ हिस्सों को अलग कर कबीरधाम जिला बनाया गया। बाद में, सन् 2022 में, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को नए जिले के रूप में अलग किया गया, जिससे राजनांदगाँव जिला क्षेत्रफल में छोटा हो गया।

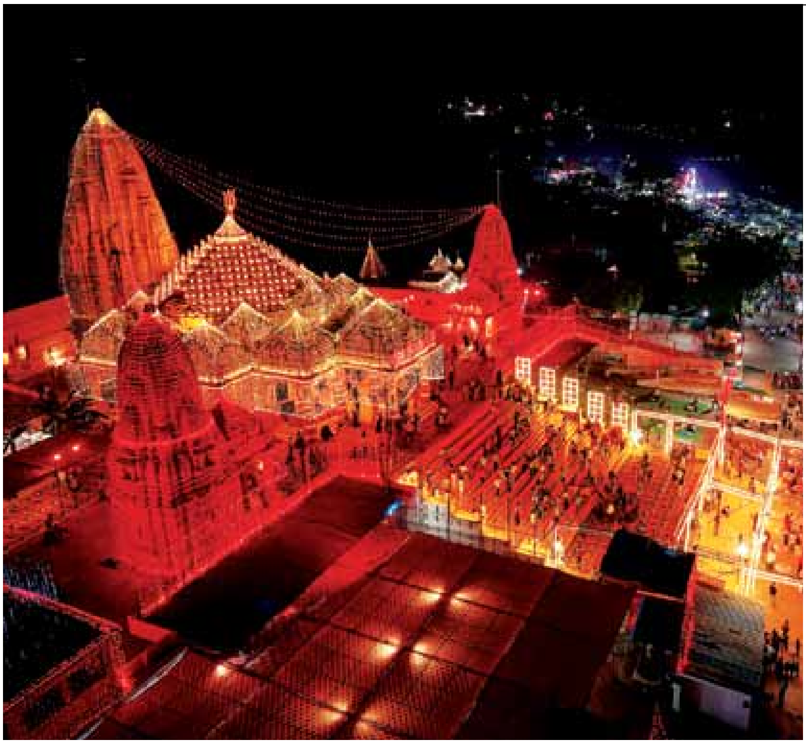

माँ बमलेश्वरी

श्रद्धा की वह चोटी जहाँ आत्मा निवास करती है

डोंगरगढ़ की पहाड़ी पर विराजमान माँ बमलेश्वरी न केवल आस्था का केन्द्र हैं, बल्कि उनका यह मंदिर श्रद्धालुओं के भीतर वह शक्ति भरता है, जिससे वे जीवन की हर चढ़ाई पार कर लेते हैं। करीब 1,000 सीढ़ियों की यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, यह एक आध्यात्मिक आरोहण है। बड़ी बमलेश्वरी और छोटी बमलेश्वरी दोनों ही माता के रूप में एक ही ऊर्जा की दो प्रतिछवियाँ हैं। नवरात्रि में जब यहाँ मेला सजता है तो लगता है जैसे पूरा नगर देवी के चरणों में अर्पित हो गया हो। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि संघर्ष में श्रद्धा की जीत का प्रतीक है।

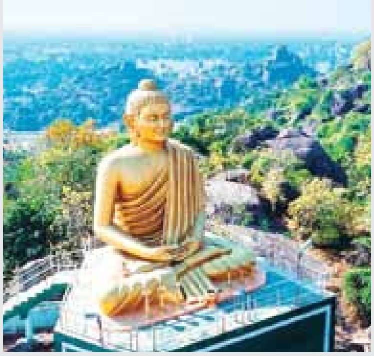

प्रज्ञागिरी – बौद्ध तीर्थ स्थल जहां हर साल फरवरी में अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है। जिसे भारत सरकार की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है।

चंद्रगिरी – जैन तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में स्थित चंद्रगिरी तीर्थ स्थल जैनियों का तीर्थ कहलाता है, जहां हर साल लाखों की संख्या में जैन धर्म के साथ दूसरे धर्म के अनुयायी भी आते हैं।

साहित्य और संस्कृति : शब्दों की धरती, विचारों व कलाकारों का उद्गम

राजनांदगाँव केवल भवनों का समूह नहीं, यह उन विचारों और भावनाओं की प्रयोगशाला है, जिनसे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ व कला को नई ऊँचाइयाँ मिली।

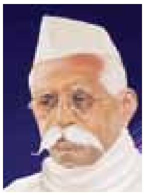

पंडित रविशंकर शुक्ल
जो स्वतंत्र भारत के पहले नेताओं में से एक थे, यहीं की मिट्टी में पले।

गजानन माधव मुक्तिबोध
जिनकी कविताएँ चेतना को झकझोरती हैं इसी शहर की गलियों से होकर निकलीं।

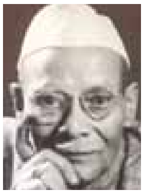

डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र
जिनका कार्य छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समझने के लिए आधारशिला है।

किशोर साहू
प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता थे।

संदीप सोपारकर
भारतीय लैटिन व बॉलरूम नर्तक, कोरियोग्राफर, अभिनेता, रेडियो जॉकी हैं।

यह शहर कलम का तीर्थ है, जहाँ हर शब्द में विचार पलते हैं और हर वाक्य में संस्कृति झलकती है।

आधुनिक विकास
जड़ों से जुड़कर भविष्य की ओर

आज का राजनांदगाँव अतीत की परंपराओं को सीने से लगाए हुए पूरी ताकत के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यहाँ के शैक्षणिक संस्थान आज युवाओं को केवल डिग्री नहीं, बल्कि दृष्टि दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी यह जिला एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है – जहाँ छोटे और मध्यम उद्योगों ने लोगों की आजीविका को नए पंख दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क और स्वास्थ्य परियोजनाएँ यहाँ बुनियादी ढाँचे को मजबूती दे रही हैं। राजनांदगाँव का विकास, उसकी संस्कृति के साथ तालमेल बिठाता हुआ – एक संतुलित समाज का सपना साकार कर रहा है।

खानपान
स्वाद में छिपा अपनापन

यहाँ का खाना केवल पेट नहीं भरता, आत्मा को भी तृप्त करता है। छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की सादगी और स्वाद में राजनांदगाँव का स्नेह और संवेदना बसती है। यहाँ का खाना एक संस्कृति की थाली है, जिसमें सादगी, स्वाद और परंपरा का परोसा जाना एक साथ होता है।

चीला: सुबह की धूप और चूल्हे की गर्मी के बीच बना यह व्यंजन जैसे दिन की शुरुआत को आशीर्वाद देता हो।

फरा: सेहत और स्वाद का सुंदर संगम जो पारंपरिक रसोई की आत्मा है।

अईरसा: त्यौहारों की मिठास, जिसमें गुड़ के साथ भावनाएँ भी घुली होती हैं।

बोरे बासी: गर्मी के दिनों में सुकून देने वाला ठंडा स्पर्श। भिगोए चावल का स्वाद।

कला और हस्तशिल्प
हाथों से बुनी हुई परंपरा

यहाँ के कलाकार बाँस और लकड़ी से वह जादू रचते हैं जो आंखों में बस जाए। कारीगरों की उँगलियाँ केवल शिल्प नहीं गढ़तीं, वे इतिहास की कारीगरी को भी जीवित रखती हैं। यहाँ के लोकनृत्य सुआ नृत्य और पंथी नृत्य सिर्फ प्रदर्शन नहीं, बल्कि समुदाय की आत्मा हैं। हर त्यौहार, हर अवसर इन नृत्यों के बिना अधूरा लगता है। यह कला राजनांदगाँव के सांस्कृतिक डीएनए में बसी हुई है।

पर्यटन स्थल
जहाँ हर मोड़ पर एक कहानी है

अंबागढ़ किला: इतिहास की ऊँचाई से वर्तमान को देखता यह किला आज भी गर्व से खड़ा है।

खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय: सुर और ताल की दुनिया का वह केंद्र, जो एशिया में अपने आप में अद्वितीय है।

डोंगरगढ़ की पहाड़ियाँ: ट्रेकिंग करने वालों के लिए प्राकृतिक आस्था और रोमांच का संगम।

अतीत की गहराई से भविष्य की ऊँचाई तक

राजनांदगाँव केवल एक शहर नहीं, यह संस्कारों की विरासत और भविष्य की उम्मीद का संगम है। यहाँ के लोग परंपराओं की चादर ओढ़े हुए हैं, लेकिन आँखों में विकास के सपने पल रहे हैं। यह शहर समय के साथ बदलता जरूर है, पर अपनी आत्मा को कभी नहीं खोता। यह है राजनांदगाँव संस्कारों की राजधानी, साहित्य की काशी और छत्तीसगढ़ की आत्मा।

साकार होगा पायलट बनने का सपना

जशपुर में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण

| जनमन रिपोर्ट |

रायपुर के बाद अब जशपुर में एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि इससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिलेगी। फिलहाल 100 युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनका पायलट बनने का सपना साकार किया जाएगा।

वाक़िफ़ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से..। शायर फ़हीम जोगापुरी के इस शेर को इन दिनों जशपुर के युवा जोश-ओ-खरोश के साथ कह रहे हैं। उन्हें एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उनका एयरफोर्स पायलट बनने का सपना साकार हो सके। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने गुजरे दिनों जशपुर के आगडीह हवाई पट्टी में थी सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी के कैडेट्स को दिए जा रहे एयरक्राफ्ट फ्लाइंग प्रशिक्षण का शुभारंभ किया तथा प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ तस्वीर भी खिंचवाई।

साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को बेहतर करियर के अवसर उपलब्ध कराने संकल्पबद्ध है। इस प्रशिक्षण से विमानन क्षेत्र में करियर बनाने हेतु युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। श्री साय ने जशपुर में पहली बार शुरू हुए विमान उड़ान प्रशिक्षण को एक ऐतिहासिक पहल बताया। उन्होंने कहा कि जशपुर अब केवल पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं, बल्कि विमानन प्रशिक्षण का नया हब भी बन रहा है। मुख्यमंत्री साय ने माइक्रो लाइट एयर स्कवाड्रन विमान का अवलोकन कर तकनीकी जानकारी ली।

अब तक राजधानी के माना स्थित स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर इस प्रशिक्षण का संचालन किया जा रहा था, लेकिन माना एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक के दबाव और 100 कैडेट्स को एयरक्राफ्ट उड़ान का प्रशिक्षण देने में कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी।

इसके बाद इस प्रशिक्षण को प्रदेश के किसी और छोटे हवाई अड्डे या रनवे पर शिफ्ट करने का निर्णय लेते हुए जशपुर के आगडीह हवाई अड्डे का चयन किया गया। यह पहली बार है जब रायपुर से बाहर जशपुर में विमान संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी अंचल के युवाओं के लिए यह न केवल एक सुनहरा अवसर है, बल्कि उनके पायलट बनने के सपने को साकार करने का मंच भी है। लगभग एक महीने तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में कुल सौ कैडेट्स को विमान उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसकी शुरुआत 35 कैडेट्स से हो चुकी है।

इस पूरे प्रशिक्षण अभियान से 10 सदस्यीय तकनीकी टीम जुड़ी है। विंग कमांडर वीके साहू ने बताया कि माह के अंत तक 100 कैडेट्स को इस विमान के उड़ान और नियंत्रण का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साहू ने बताया कि एयर फोर्स और एविएशन के क्षेत्र में करियर के रूप में इसे चुनने वाले युवाओं के लिए यह प्रशिक्षण बेहद कारगर है। साहू खुद बसना क्षेत्र के लाखौली के निवासी हैं और सबसे पहले उन्होंने भी एनसीसी कैडेट्स के रूप में उड़ान भरी थी, जो आगे चलकर उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।

एयर फोर्स और एविएशन के क्षेत्र में करियर के रूप में इसे चुनने वाले युवाओं के लिए यह प्रशिक्षण बेहद कारगर है। प्रशिक्षु नितेश प्रजापति ने बताया कि जशपुर का स्वच्छ और खूबसूरत वातावरण उड़ान प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त है। उन्होंने कहा, "मेरा सपना एयरफोर्स पायलट बनने का है और यह प्रशिक्षण मुझे उस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।" एक अन्य प्रशिक्षणार्थी प्रांशु चौहान ने बताया कि जशपुर में एयर ट्रैफिक साफ-सुथरा रहता है, जिससे उड़ान में कोई बाधा नहीं आती। रनवे भी पूरी तरह से क्लियर रहता है, जिससे प्रशिक्षण बिना किसी रुकावट के संचालित हो रहा है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच प्रशिक्षण लेना हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा।"

ट्विन-सीटर SW-80 विमान से दी जा रही ट्रेनिंग

आगडीह हवाई पट्टी की लंबाई 1200 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। यहाँ सिंगल इंजन ट्विन-सीटर वायरस SW-80 विमान से कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 20,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक उड़ सकता है। हालांकि, फिलहाल प्रशिक्षण के लिए 1,000 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ान संचालित की जा रही है। कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि एनसीसी एयर विंग के "सी" सर्टिफिकेट में उच्च ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले कैडेट्स सीधे एयरफोर्स इंटरव्यू के लिए पात्र माने जाते हैं, जिससे यह प्रशिक्षण उनके सुनहरे भविष्य की नींव रखता है।

एक कैडेट्स के लिए एयरफोर्स या एविएशन क्षेत्र में जाने वाले युवा के लिए यह प्रशिक्षण फ्लाइंग स्कूल में प्रवेश के लिए सहायक सिद्ध होता है। जशपुर हवाई पट्टी पर चिकित्सा स्टाफ के साथ एंबुलेंस और फायर फाइटिंग दस्ते के साथ तमाम तरह की सुरक्षा और व्यवस्थाएँ यहाँ की गई हैं। युवाओं को उड़ान भरने और रनवे पर लैंड करने से लेकर, विमान के कॉकपिट से लेकर हर हिस्से और विमान के नियंत्रण को लेकर सभी बेसिक जानकारी दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को हर क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन और अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हमेशा युवाओं के सपनों को पंख देने के सफलतम प्रयास किए हैं। 10वीं की कक्षाओं में मेरिट आने वाले विद्यार्थियों को साय राज्य सरकार के विमान से निःशुल्क हवाई यात्रा करवाते रहे हैं। पिछले साल स्वामी आत्मानंद स्कूल रघुनाथ नगर की नन्हीं बच्ची स्मृति ने जब हेलीकॉप्टर में घूमने की जिद की तो सीएम साय ने उसकी ख्वाहिश तुरंत पूरी कर दी थी।

एयर कनेक्टिविटी का विस्तार

छत्तीसगढ़ अब एवीएशन हब बनने जा रहा है। यहाँ एयर कनेक्टिविटी का विस्तार लगातार हो रहा है। बिलासपुर–दिल्ली और बिलासपुर–कोलकाता सीधी हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। जगदलपुर से जबलपुर के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू हो गई है। बिलासपुर से हैदराबाद के लिए भी विमान सेवा प्रारंभ होना है। इसके साथ ही बिलासपुर हवाई अडडा को अपग्रेड करने तथा नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी है।

देश का पॉवर हब बनने को तैयार छत्तीसगढ़

तीन लाख करोड़ का एमओयू, खुलेंगे रोजगार के द्वार, न्यूक्लियर युग में प्रवेश की तैयारी

थर्मल, हाइड्रो, सोलर और न्यूक्लियर पॉवर से प्रदेश बनेगा और मजबूत

| जनमन रिपोर्ट |

प्रदेश की विष्णु देव साय सरकार की ओर से राज्य के विकास और गुडगवर्नेंस को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मार्च माह में प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित इन्वेस्टर्स समिट ने इस बात के पूर्ण संकेत दे दिए हैं कि पॉवर के मामले में अब छत्तीसगढ़ केवल आत्मनिर्भर ही बनकर नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले पाँच से सात वर्षों में यह देश का पॉवर सेंटर या पॉवर हब बनेगा। खास बात यह भी है कि छत्तीसगढ़ अब न्यूक्लियर दौर में प्रवेश करने को तैयार है। 4200 मेगावाट के न्यूक्लियर पॉवर प्रोडक्शन का एमओयू एनटीपीसी के साथ प्रदेश सरकार ने कर लिया है, जो कि 80 हजार करोड़ रुपये का है।

कहाँ कितने का करार

- ₹80 हजार करोड़ का निवेश परमाणु ऊर्जा में
- ₹1 लाख 7 हजार 840 करोड़ ताप विद्युत क्षमता को मजबूत करने के लिए
- ₹10 हजार करोड़ सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के विस्तार के लिए
- ₹4 हजार 100 करोड़ पीएम कुसुम योजना, किसानों के बीच सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
- ₹57 हजार 046 करोड़ पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएँ, ग्रिड स्थिरता के लिए ऊर्जा भंडारण में
- ₹3 हजार 200 करोड़ क्रेडा सौर पहलः सौर ऊर्जा विस्तार के लिए
- ₹6 हजार करोड़ पीएम सूर्य योजना के तहत सौर छत परियोजनाएँ
- ₹2 हजार 500 करोड़ सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए
- ₹2 हजार 600 करोड़ बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के लिए
- ₹17 हजार करोड़ पॉवर ट्रांसमिशन-डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को उन्नत करने के लिए
- ₹10 हजार 800 करोड आरडीएसएस (वितरण क्षेत्र योजना) के तहत वितरण बुनियादी ढाँचे में सुधार के लिए

छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में यह निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊँचाइयों तक ले जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो।

विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

वर्तमान की बात करें तो छत्तीसगढ़ पहले से ही सरप्लस स्टेट के रूप में 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है जो देश के औसत से कहीं ज्यादा है। हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट प्रति घंटे बिजली मिल रही है। इस इन्वेस्टर्स समिट में थर्मल, सोलर, हाइड्रो और न्यूक्लियर पॉवर प्रोडक्शन के लिए आए कुल तीन लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों ने प्रदेश सरकार की प्राथमिकता के साथ उसकी दूरदर्शिता व राज्य को एक नए फलक पर ले जाने की दृढ़ता पर भी मुहर लगा दी है।

क्यों निवेशक हो रहे आकर्षित

- डीपीआईआईटी और वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्टेट रैंकिंग में शामिल है छत्तीसगढ़
- कंसिस्टेंट छत्तीसगढ़ः 301 रिफॉर्म्स में से 252 का क्रियान्वयन
- 24 में से 12 व्यापार सुधार क्षेत्रों में शत-प्रतिशत क्रियान्वयन
- बेस्ट ऑनलाइन सिंगल विंडो सिस्टम
- मध्य क्षेत्र में स्थित, सात सीमावर्ती राज्यों के 500 मिलियन लोगों तक पहुँच देता है जो कि देश की कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है जिनका देश की जीडीपी में 38 प्रतिशत योगदान है।

क्यों महत्वपूर्ण है

प्रदेश के इतिहास में पहली बार पॉवर सेक्टर में तीन लाख करोड़ रुपये का एमओयू साइन हुआ है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न माध्यमों जैसे सोलर, थर्मल, न्यूक्लियर व हाइड्रो से न सिर्फ बिजली का उत्पादन होगा बल्कि इसके ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक मजबूत इंफ्रास्टक्चर तैयार करने की योजना है ताकि आने वाले समय में उत्पादित बिजली को निर्बाध तरीके से सही गंतव्य तक पहुँचाया जा सके।

जहाँ नहीं पहुँचे उद्योग वहाँ 33 हजार करोड़ का निवेश

प्रदेश के ऐसे जिले या इलाके जहाँ अब तक उद्योग नहीं पहुँच सके हैं यानी वहाँ कोई औद्योगीकरण नहीं हुआ है, प्रदेश सरकार अब वहाँ भी उद्योग के माध्यम से विकास को पहुँचाने की तैयारी कर रही है। वो माध्यम जलविद्युत का है। अभी तक की स्थिति को देखें तो प्रदेश में अब तक जो औद्योगीकरण हुआ है वो हावड़ा-मुंबई रेल लाइन या चांपा-कोरबा रेल लाइन के आसपास यानी दस से पंद्रह किलोमीटर के इर्द-गिर्द ही स्थित हैं। वर्तमान में पंप स्टोरेज पॉलिसी के तहत सार्वजनिक सेक्टर के टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कॉर्पोरेशन, सतलज जल विद्युत निगम व प्रदेश की बिजली कंपनी ने लगभग 33 हजार करोड़ का प्रस्ताव दिया है। ये पंप स्टोरेज प्लांट उन क्षेत्रों में आ रहे हैं जहाँ औद्योगीकरण अब तक नहीं हो सका है। इसमें जशपुर, बलरामपुर, गरियाबंद आदि जिले शामिल हैं। इन इलाकों में इतने बड़े निवेश का फायदा यह होगा कि यहाँ विकास की राह तो खुलेगी ही साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी आएँगे। पंप विद्युत क्षेत्र में निजी कंपनियों ने भी अपनी विशेष रुचि दिखाई है। इसमें जिंदल पॉवर की आनुषांगिक कंपनी जिंदल रिन्युएबल एनर्जी सहित एक अन्य कंपनी रिनी विद्युत ने रायगढ़, बिलासपुर और कबीरधाम जिले में यूनिट लगाने का प्रस्ताव दिया है।

सौर एनर्जी में भी व्यापक निवेश

सोलर पॉवर में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 983 मेगावाट के प्लांट लग रहे हैं। क्रेडा के पास 800 मेगावाट का प्रस्ताव आ चुका है। इसकी लागत 3200 करोड़ रुपये है, आने वाले समय में ये और बढ़ता ही जाएगा। वहीं पीएम सूर्यघर योजना को लेकर भी प्रदेश ने गंभीरता दिखाई है। इसके तहत अब राज्य की ओर से भी लाभ दिए जाने की तैयारी है। लगभग छह लाख घरों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है इससे आने वाले 3 वर्षों में 1200 मेगावाट पॉवर जनरेट करने की तैयारी है इसमें छह हजार करोड़ का निवेश होगा। इसी प्रकार सरकारी स्कूल, बिल्डिंग, कॉलेज, अस्पताल सहित प्रायवेट भवनों में भी सोलर प्लांट लगाने की तैयारी है। इसके तहत 500 मेगावाट का टारगेट रखा गया है जिसमें करीब 2500 करोड़ का निवेश होगा।

युवाओं को पॉवर प्रोड्यूसर बनाने की तैयारी

सोलर पॉवर के तहत प्रदेश में युवाओं को आंत्रप्रेन्योर बनाने की तैयारी की जा रही है। पीएम कुसुम योजना के तहत इसे साकार किया जाएगा। पीएम कुसुम योजना में कंपोनेंट ए के तहत आधा से 2 मेगावाट, कंपोनेंट बी के तहत सिंचाई पंपों के सोलराइजेशन व कंपोनेंट सी में दो से दस मेगावाट बिजली पैदा करने का प्रावधान है। प्रदेश की विष्णु देव साय की सरकार इसी योजना से प्रदेश के युवाओं को आंत्रप्रेन्योर या पॉवर प्रोड्यूसर बनाने की तैयारी कर रही है। इस पूरे योजना में 4100 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। पहले पॉवर जनरेट करने का

कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

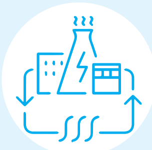

थर्मल एनर्जी

अदानी पॉवर 66,720 करोड़ रुपये खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600-1600 मेगावाट के तीन थर्मल पॉवर प्लांट लगाएगा। जिंदल पॉवर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

परमाणु ऊर्जा

परमाणु के क्षेत्र में एनटीपीसी ने 80,000 करोड़ रुपये की लागत से 4200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई है। इससे छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन की शुरुआत होगी।

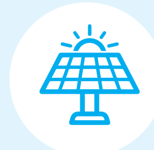

सोलर एनर्जी

जिंदल पॉवर और एनटीपीसी ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपये खर्च कर 2500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेंगे। इसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल होंगे। पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपये की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएँगे।

सरकारी कंपनियाँ एनटीपीसी और सीएसपीजीसीएल 41,120 करोड़ रुपये की लागत से 4500 मेगावाट बिजली उत्पादन करेंगी।

बैटरी स्टोरेज मामले में देश का पहला राज्य

पॉवर सेक्टर में गर्व की बात यह भी है कि बैटरी स्टोरेज प्लांट के मामले में छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ इसे स्थापित किया गया है। राजनांदगाँव में 40 मेगावॉट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज यूनिट लगाई गई है। प्रदेश सरकार भविष्य में पीक ऑवर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए करीब 2 हजार मेगावॉट क्षमता की बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्लांट लगाने की तैयारी में है। इसके लिए स्थान का चयन किया जा चुका है।

कार्य बड़ी कंपनियाँ करती थीं क्योंकि लागत इसमें ज्यादा आती थी। इसके कारण छोटा उद्यमी इससे बाहर हो जाता था। एक अनुमान के मुताबिक आधा मेगावाट तक सोलर पॉवर जनरेट करने के लिए लगभग दो करोड़ व दस मेगावाट तक के लिए 40 करोड़ रुपये का निवेश आता है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि यहाँ के युवा या उद्यमी बिजली उत्पादन में अपना योगदान दें, ताकि आने वाले समय में वो बड़े उद्योगपति बन सकें।

उत्पादन के साथ वितरण पर फोकस

प्रदेश एक ओर जहाँ विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक बिजली उत्पादन की तैयारी है तो दूसरी ओर इस तैयार बिजली के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी पुख्ता कार्ययोजना तैयार है। इसके तहत 17 हजार करोड़ रुपये का निवेश राज्य बिजली कंपनी व पॉवरग्रिड कार्पोरेशन की ओर से किया जाएगा। पॉवर के प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन के बाद बारी आती है डिस्ट्रीब्यूशन की, इस सेक्टर को मजबूत करने का कार्य वर्तमान में जारी है ताकि तैयार बिजली को सही गंतव्य तक आसानी से पहुँचाया जा सके। वर्तमान में सेंट्रल सेक्टर की एक योजना आरडीएसएस के तहत कार्य जारी है यह साढ़े सात हजार करोड़ का प्रोजेक्ट है इसमें 2200 करोड़ का कार्य हो चुका है। आने वाले समय में 3400 करोड़ के कार्य और आरंभ होंगे।

कबीरधाम
प्रकृति, इतिहास और आस्था का संगम

| जनमन रिपोर्ट |

छत्तीसगढ़ का कबीरधाम जिला विविधताओं से भरा एक अनूठा पर्यटन क्षेत्र है, जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक विरासत और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यहाँ स्थित भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का "खजुराहो" कहा जाता है। वहीं चौरागढ़ किला वीरता और स्थापत्य का प्रतीक है। बोड़ला महादेव मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है जबकि सरोधा दादर अपनी शांत वादियों, जैव विविधता और ट्रेकिंग रूट्स के लिए जाना जाता है। साथ ही, देवान पटपर अपने रहस्यमय चुंबकीय प्रभाव के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। इन स्थलों के विकास के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे कबीरधाम अब राज्य के उभरते पर्यटन हॉटस्पॉट्स में शामिल हो गया है। इस बेहतरीन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से समझिए ताकि आप यहाँ दौरा करें तो आपको क्या खास देखने, घूमने और सुविधाओं के रूप में मिलेगा।

भोरमदेव मंदिर : छत्तीसगढ़ का खजुराहो

कबीरधाम शहर से करीब 18 किमी दूर भोरमदेव मंदिर एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे इसकी अद्भुत वास्तुकला व मूर्तिकला के कारण छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में फणिनागवंशी शासक गोपालदेव के संरक्षण में नागर शैली में हुआ था। यह मंदिर धार्मिक आस्था और कलात्मक धरोहर दोनों का अद्वितीय संगम है।

मुख्य आकर्षण : शिल्पकला से सजे मंदिर की भव्यता। हर साल आयोजित भोरमदेव महोत्सव। स्वच्छ वातावरण, बैठने, पार्किंग, पेयजल और भोजन की सुविधाएँ। पास में होटल, धर्मशालाएँ और पुलिस चौकी उपलब्ध।

स्थल का विस्तार व विकास

- पर्यटन विकास के तहत मंदिर क्षेत्र में बुनियादी ढाँचे का विस्तार।
- रायपुर-भोरमदेव सड़क चौड़ीकरण।
- आकर्षक लाइटिंग और रात्रिकालीन शो की व्यवस्था।

सरोधा दादर : प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अद्भुत संगम

सरोधा दादर, घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा एक सुंदर पर्यटन स्थल है। इसका धार्मिक इतिहास भले न हो, लेकिन जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता इसे खास बनाती है। समुद्र तल से ऊँचाई पर होने के कारण यहाँ का मौसम सालभर सुहावना रहता है। क्षेत्र में दुर्लभ पक्षी और वन्यजीव पाए जाते हैं। शांत वातावरण ध्यान और योग के लिए आदर्श है। कैंपिंग और एडवेंचर एक्टिविटी के लिए सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

पर्यटकों के लिए आकर्षण : ट्रेकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स का रोमांच। दुर्लभ पक्षियों की प्रजातियाँ देखने का अवसर। मानसून में झरने और जल स्रोतों की छटा। हिरण, तेंदुए जैसे वन्यजीवों का निवास स्थल। ट्रेकिंग और कैंपिंग सेवाओं के लिए टूर ऑपरेटर। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता।

नई सुविधाएँ

- इको-टूरिज्म को बढ़ावा और संसाधनों का संरक्षण।
- ट्रेकिंग मार्ग और सड़कों का विकास।
- होमस्टे योजना से स्थानीय रोजगार को बढ़ावा।
- सुरक्षा और गाइड सेवाओं को बेहतर बनाया गया।

मड़वा महल : प्रेम और शौर्य का प्रतीक

यह मंदिर अपनी खजुराहो जैसी मिथुन मूर्तियों और जटिल नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। मंदिर का इतिहास कलचुरी और नांगवंशी शासकों के साथ-साथ गोंड आदिवासियों की सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा है। यह छत्तीसगढ़ की समृद्ध ऐतिहासिक और स्थापत्य विरासत का प्रतीक है। कबीरधाम जिले में स्थित मड़वा महल 14वीं शताब्दी में सन 1349 ई. में नागवंशी राजा रामचंद्र देव और अंबिका देवी के विवाह के उपलक्ष्य में शासकों द्वारा बनाया था। यह ऐतिहासिक स्थल इनकी शादी के उपलक्ष्य में निर्मित विवाह मंडप के रूप में जाना जाता है, जिससे इसका नाम "मड़वा महल" पड़ा। यह भोरमदेव मंदिर के पास स्थित है। इसकी स्थापत्य शैली खजुराहो व कोणार्क मंदिरों से प्रभावित लगती है। महल की दीवारों पर उकेरी गई मूर्तियाँ नागवंशी काल की समृद्ध संस्कृति को दर्शाती हैं, जिससे यह स्थल ऐतिहासिक और कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है।

पर्यटक आकर्षण: नागर शैली की प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला। भोरमदेव मंदिर के समीप होने के कारण एक ही यात्रा में दो ऐतिहासिक स्थलों का अनुभव। हरियाली और पहाड़ियों से घिरा प्राकृतिक सौंदर्य। इतिहास प्रेमियों व शोधकर्ताओं के लिए आकर्षक स्थान।

सुविधाएँ

- अच्छी सड़क सुविधा और परिवहन व्यवस्था।
- नजदीकी होटल व लॉज में ठहरने की सुविधा।
- गाइड और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध।

चिल्फी घाटी
छत्तीसगढ़ का स्वर्ग

सतपुड़ा पर्वतमाला में स्थित चिल्फी घाटी प्राकृतिक सौंदर्य, हरियाली और ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल ट्रेकिंग, फोटोग्राफी और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद लोकप्रिय है। मानसून के दौरान झरनों की सुंदरता इसे और मनमोहक बनाती है।

पर्यटक आकर्षण: ट्रेकिंग ट्रेल, जलप्रपात, शांत वातावरण। बर्ड वॉचिंग व पिकनिक स्पॉट।

सुविधाएँ

- व्यू पॉइंट, गाइड, विश्राम स्थल
- पास के गाँवों में होटल, लॉज, होमस्टे
- बेहतर सड़क कनेक्टिविटी

नई पहल

- इको-टूरिज्म हब के रूप में विकास
- सुरक्षा व सूचना केंद्र
- स्थानीय रोजगार को बढ़ावा

भोरमदेव अभयारण्य : प्रकृति और रोमांच का संगम

कबीरधाम जिले में स्थित यह अभ्यारण्य 326.87 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है। सतपुड़ा-मैकल की पहाड़ियों में बसे इस क्षेत्र में साल, सागौन और बाँस के घने जंगल हैं। यहाँ बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर, चीतल जैसे अनेक वन्यजीव और अनेक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं।

पर्यटक आकर्षण: जंगल सफारी, ट्रेकिंग और कैंपिंग। बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी। भोरमदेव मंदिर के पास स्थित होने से धार्मिक पर्यटन से भी जुड़ाव

सुविधाएँ

- सफारी, गाइड, विश्रामगृह, होमस्टे और रिसॉर्ट्स
- सड़क मार्ग की सुविधा और वन संरक्षण योजनाएँ

नई पहल

- इको-टूरिज्म केंद्र के रूप में विकास
- सड़क और परिवहन सुधार
- वन्यजीव संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर

रानी दहरा: प्रकृति और इतिहास की अद्भुत छाया

रानी दहरा जलप्रपात कबीरधाम जिला मुख्यालय से छत्तीसगढ़ राज्य के जबलपुर रोड तक लगभग 35 किमी दूर है। यह कबीरधाम की बोड़ला तहसील से 15 किमी दूर है। रियासत काल में यह दर्शनीय स्थल राजपरिवार के लोगों का मुख्य मनोरंजन स्थल हुआ करता था।

रानी दहरा मैकल पर्वत के आगोश में स्थित है। पहाड़ी से बारिश का पानी लगातार बहता रहता है, जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहां पहुंचने के लिए बोडला से पक्की सड़क है। नतीजतन, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पहाड़ी से बहता जलप्रपात हिलता-डुलता प्रतीत होता है। इसके चारों ओर का वातावरण काफी शांत है, जिससे वसंत की आवाज साफ सुनाई देती है।

मुख्य आकर्षण: सुंदर झरने और प्राकृतिक जल स्रोत, ट्रेकिंग व जंगल सफारी और फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्थल, पक्षी प्रेमियों के लिए दुर्लभ प्रजातियाँ, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व से जुड़ा स्थल।

नई सुविधाएँ और विकास

- सड़क और परिवहन का उन्नयन
- साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रेकिंग मार्ग विकसित
- स्थानीय होमस्टे और गाइड सेवा के माध्यम से रोजगार सृजन
- पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान

देवान पटपर: प्राकृतिक रहस्य और चुंबकीय आकर्षण का केंद्र

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के कवर्धा नगर से लगभग 40 किमी दूर स्थित देवान पटपर एक रहस्यमय और आकर्षक स्थल है। यह जगह एक अद्भुत चुंबकीय प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ सड़क पर खड़ी गाड़ियाँ अपने आप पीछे की ओर खिसकने लगती हैं। वैज्ञानिक इसे ग्रैविटी हिल इफेक्ट कहते हैं।

प्राकृतिक और भूगर्भीय विशेषताएँ : यह स्थान एक ढलानदार सड़क पर स्थित है, जहाँ दृष्टि का भ्रम (optical illusion) चुंबकीय प्रभाव जैसा अनुभव कराता है। हरे-भरे पहाड़ी इलाके और घने जंगल इस स्थल की सुंदरता को बढ़ाते हैं। शांत वातावरण और प्रकृति की गोद में स्थित यह स्थान ट्रेकिंग और शांति की तलाश करने वालों के लिए उपयुक्त है। क्षेत्र का रहस्यात्मक अनुभव पर्यटकों को रोमांच और जिज्ञासा से भर देता है।

पर्यटकों के लिए आकर्षण

- **चुंबकीय अनुभव** – गाड़ियों का बिना इंजन के ढलान पर ऊपर की ओर खिसकना।
- **नेचर ट्रेल्स और फोटोग्राफी** – हरियाली, पहाड़ी दृश्य और रहस्य को कैमरे में कैद करने का मौका।
- **लोककथाओं से जुड़ाव** – स्थानीय लोग इसे दैवीय शक्ति से जोड़ते हैं, जिससे धार्मिक जिज्ञासा भी जुड़ी रहती है।
- **एडवेंचर और अन्वेषण** – युवा पर्यटकों के लिए यह खोज और रोमांच का स्थान है।

सुविधाएँ

- सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।
- पर्यटकों की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर मार्गदर्शक उपलब्ध हैं।
- सीमित लेकिन आवश्यक खानपान और विश्राम की सुविधाएँ पास के गाँवों में उपलब्ध हैं।
- प्रशासन द्वारा क्षेत्र की साफ-सफाई और सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

विस्तार

- देवान पटपर को एक वैज्ञानिक-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- पर्यटकों के लिए संकेतक, जानकारी बोर्ड और व्यू पॉइंट तैयार किए गए हैं।
- क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सड़क और परिवहन सुविधाओं में सुधार हुआ है।
- स्थानीय युवाओं को गाइड और हॉस्पिटैलिटी सेवाओं में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा जा रहा है।

आईआईएम में विधायकों की पाठशाला

। जनमन रिपोर्ट ।

देश के प्रतिष्ठित नीति निर्माता, शिक्षाविद और विचारकों ने छत्तीसगढ़ के विधायकों को नीतिगत फैसले लेने, सुशासन और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुपयोगी टिप्स दिए। इसके पहले राज्य के मंत्रियों ने प्रशिक्षण हासिल किया था।

विधायकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में से एक आईआईएम रायपुर में, दो दिवसीय 'मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम' आयोजित किया गया जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह तथा नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने किया।

कार्यक्रम की शुरूआत में आईआईएम के निदेशक प्रो. राम कुमार ककानी ने अतिथियों को पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को लेकर आईआईएम ने राज्य सरकार के साथ मिलकर यह आयोजन किया। हम शिक्षा और प्रशासन की दूरी को पाटने पर यकीन रखते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम रणनीतिक, संवाद तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने तथा क्षमता बढ़ाने में जनप्रतिनिधियों के लिए लाभकारी होगा। यह प्रशिक्षण अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी है।

मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि सतत् सीखना ही प्रभावी नेतृत्व की पहचान होती है। इसके पूर्व मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जा चुका है। इसकी सफलता के बाद विधायकों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्य सरकार ने आईआईएम रायपुर से अनुबंध किया है नतीजतन जनप्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसका उद्देश्य विधायकों को नेतृत्व कौशल, प्रबंधन रणनीतियों और नीति निर्माण की बारीकियों से अवगत कराना है।

कई सत्रों में नेतृत्व विकास, प्रभावी संचार, संसाधन प्रबंधन और निर्णय लेने की कला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर सामूहिक चर्चा और शंका समाधान भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के समापन में कहा कि यह कार्यक्रम हमारी विधानसभा के भविष्य को मजबूत बनाने और विधायक के कर्तव्यों को समझने का एक महत्वपूर्ण कदम है। विधायक का मुख्य कार्य जनता से संवाद और उनके मुद्दों का समाधान करना है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे विधायकगण अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक समर्पित हो सकेंगे।

संसदीय कार्यमंत्री केदार कश्यप ने सभी विधायक प्रशिक्षणार्थियों को अपनी शुभकामनाएँ दीं। आधा दर्जन से अधिक सत्रों में प्रदेश की दस से अधिक महिला विधायकों ने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का लाभ उठाया। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में विशेष विशेषज्ञों में डॉ.संजीव पाराशर, सुमीत गुप्ता, डॉ कमल जैन, डॉ सत्यशिव दास, पुष्प कुमार जोशी, डॉ शांतनु बत्रा, डॉ. विनोद मिलिंद, डॉ अर्चना पाराशर इत्यादि ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया।

| जनमन रिपोर्ट |

अबूझमाड़ का विकास हमारी प्राथमिकताः सीएम साय

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के सुदूर वनांचल अबूझमाड़ पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो रहा है। एक ओर जहाँ नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन के जरिए कार्रवाई की जा रही है, वहीं अब दूरस्थ अंचल के गाँवों में सरकार अपनी पहुँच स्थापित करने में जुटी है। धीरे-धीरे बेहद नक्सल प्रभावित इलाकों को मुक्त कर वहाँ शासन के विकास की पहुँच स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है।

नारायणपुर के अबूझमाड़ से आए 120 बच्चों ने विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ.रमन सिंह, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा तथा वनमंत्री केदार कश्यप से मुलाकात की। ये बच्चे 'स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना' के तहत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चों से संवाद किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार अबूझमाड़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री

अबूझमाड़ में तेजी से हो रहे विकास कार्य

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि अबूझमाड़ के गाँवों में सड़क निर्माण, मोबाइल टावर लगाने, स्कूलों के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 'नियद नेल्ला नार योजना' के तहत वहाँ तेजी से बुनियादी ढाँचे का विकास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में अबूझमाड़ सहित पूरे बस्तर क्षेत्र के विकास को लेकर व्यापक चर्चा हुई। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजना पर काम कर रही हैं।

आपकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य हमारी जिम्मेदारी

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि अबूझमाड़ के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे अपने क्षेत्र और प्रदेश के विकास में योगदान दे सकें। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सरकार आपके साथ है और हर संभव मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अबूझमाड़ में बेहतर स्कूल, छात्रावास, स्वास्थ्य केंद्र और रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

साय ने कहा कि अबूझमाड़ वर्षों तक विकास की धारा से वंचित रहा, लेकिन हमारी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि यहाँ के हर गाँव तक शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और संचार जैसी बुनियादी सुविधाएँ पहुँचे। उन्होंने भ्रमण पर आए बच्चों से कहा कि आपका उज्ज्वल भविष्य ही हमारी प्राथमिकता है।

दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई में आखेट नृत्यों की अद्भुत परंपरा

| जनमन रिपोर्ट |

दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई एक ऐसा जनजातीय उत्सव है जिसकी ख्याति देश-विदेश तक है। यह एक दस दिवसीय उत्सव है जो बस्तर की अधिष्ठात्री देवी माई दंतेश्वरी की आराधना से जुड़ा है। 600 वर्षों से चली आ रही यह परंपरा आदिवासियों के शिकार नृत्यों के लिए मशहूर है। यहाँ माँ दंतेश्वरी के साथ होली मनाने के लिए बस्तर के अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा से भी सैकड़ों देवी-देवता के लाठ और छत्र लेकर आदिवासी पहुँचते हैं।

माई दंतेश्वरी की परंपरा से जुड़ा है दस दिवसीय उत्सव

यहाँ होली मनाने के लिए जुटते हैं पड़ोसी राज्यों के देवी-देवता

माँ दंतेश्वरी के सम्मान में दंतेवाड़ा में आयोजित फागुन मड़ई बस्तर संभाग का एक प्रसिद्ध आदिवासी सांस्कृतिक मेला है। इसकी शुरुआत बस्तर के राजाओं द्वारा शिकार के लिए माँ दंतेश्वरी की अनुमति लेने से हुई थी। वर्तमान में शिकार की परंपरा का नाट्य रूपांतर कर मेले में इसका प्रदर्शन किया जाता है। शिकार नृत्यों को देखने के लिए हजारों की संख्या में नागरिकों की भीड़ जुटती है। ताड़ के पत्तों से होलिका दहन तथा टेसू के फूलों से बने रंग से माँ दंतेश्वरी के साथ अन्य देवी-देवताओं के होली खेलने की परंपरा इस उत्सव का आकर्षण होता है। बस्तर की संस्कृति व परंपरा को प्रदर्शित करने वाले इस आयोजन में एक हजार से अधिक देवी देवताओं की उपस्थिति अद्भुत अनुभव होता है। रंग भंग अर्थात होली खेलने के बाद बाहर से आए देवी-देवताओं को विदाई दी जाती है जिसमें उन्हें साड़ी, गमछा, लिफाफा सहित मिट्टी की कोड़ी भेंट की जाती है। बस्तर राजपरिवार, जिला प्रशासन तथा आम नागरिकों के सहयोग से प्रतिवर्ष यह आयोजन किया जाता है।

फागुन मड़ई का आयोजन फागुन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी से लेकर चौदस तक किया जाता है। इस वर्ष 6 से 15 मार्च तक दंतेवाड़ा में फागुन मड़ई उत्सव की धूम रही। इस उत्सव के दौरान प्रतिदिन माई दंतेश्वरी देवी की डोली को हर्ष फायर सलामी दी जाती है। माई जी की डोली प्रतिदिन नगर भ्रमण पर निकलती है जिसे देखने के लिए हजारों श्रद्धालु सड़क के किनारे एकत्र होते हैं।

फागुन मंड़ई उत्सव की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन दंतेश्वरी मंदिर के सामने अष्टधातु से निर्मित त्रिशूल स्तंभ की स्थापना के साथ होती है। इसी दिन दोपहर को आमा मऊड रस्म का निर्वहन किया जाता है जिसमें माँ दंतेश्वरी के छत्र को नगर दर्शन के लिए निकाला जाता है। यहाँ माता को आम के बौर अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद मेंडका डोबरा मैदान में स्थित देवकोठी में देवी का छत्र लाया जाता है। यहाँ छत्र को सलामी देने के बाद दीप प्रज्ज्वलित कर कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के पश्चात फागुन मड़ई उत्सव की धूम शुरू होती है। माँ दंतेश्वरी के पुजारी को पटेल अपने हाथों से भंडारीन फूल की पगड़ी बाँधते हैं जिसे फूलपागा कहा जाता है। इसके पश्चात माई जी की डोली को आमंत्रित देवी-देवताओं के लाठ और छत्र के साथ नगर परिभ्रमण के लिए निकाला जाता है। देवी की पालकी को नारायण मंदिर लाया जाता है तथा फाग गीत गाते हुए वापस दंतेश्वरी मंदिर पहुँचाया जाता है। पहले दिन ही रात को ताड़ फलंगा धोनी रस्म अदा की जाती है। इसमें ताड़ के पत्तों को माँ दंतेश्वरी सरोवर में धोकर मंदिर में रखा जाता है। इन्हीं पत्तों का उपयोग होलिका दहन में किया जाता है।

बस्तर दशहरा की ही तरह दंतेवाड़ा की फागुन मड़ई का संबंध भी रियासतकाल से है। बस्तर राजपरिवार के उत्तराधिकारी को माँ दंतेश्वरी का प्रथम पुजारी माना जाता है। फागुन मड़ई में माता के पुजारी ही नगर परिभ्रमण में डोली के साथ चलते हैं किंतु कभी कभार राजपरिवार के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। फागुन मड़ई में दूसरे दिन खोर खुंदनी की रस्म अदा की जाती है। इस दौरान पुनः माई जी की डोली को नगर भ्रमण कराया जाता है। तीसरे दिन नाच माडनी की रस्म का आयोजन किया जाता है। इसमें मांदर व नगाड़े की थाप पर मंदिर के सेवादार मंदिर के सामने नृत्य का प्रदर्शन करते हैं।

शिकार नृत्यों की अद्भुत छटा

फागुन मड़ई का प्रमुख आकर्षण शिकार नृत्य होते हैं। लम्हामार यानी खरगोश का शिकार, कोडरीमार यानी कोतरी का शिकार, चीतलमार यानी चीतल का शिकार तथा गँवरमार यानी गौर का शिकार आदि नृत्यों में जानवरों का स्वांग रचा जाता है। तूम्बे से बने मुखौटों से आदिवासी विभिन्न रूप धारण करते हैं और शिकार नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। शिकार नृत्यों में सबसे लोकप्रिय गँवरमार होता है। इसे देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इसमें एक पात्र गँवर का रूप लेकर अभिनय करता है। अन्य नर्तक हाका लगाकर उसके इर्दगिर्द घेरा डालते हैं। शिकार से बचने के लिए गँवर छिप जाता है। बाद में जिसपर देवी की कृपा होती है वह गँवर को तलाश लेता है। मंदिर के पुजारी फायर कर गँवर का प्रतीकात्मक शिकार करते हैं। आखेट जनजातीय परंपरा का प्रमुख हिस्सा होते हैं। इसका प्रदर्शन ही फागुन मड़ई की विशेषता है।

आँवरामार की परंपरा

ब्रज के बरसाना और नंदगाँव में लठमार होली की तर्ज पर दंतेवाड़ा में आंवरामार होली मनाई जाती है। गँवरमार नृत्य के अगले दिन अर्थात फागुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को यह रस्म अदा की जाती है। इस दिन माई जी की डोली के साथ दंतेश्वरी मंदिर के प्रधान पुजारी को पालकी में बिठाकर नगर भ्रमण कराया जाता है। माता की पालकी में आँवला फल अर्पित किए जाते हैं। भ्रमण के पश्चात पुजारी, सेवादार, बारह-लंकवार व आमजन दो समूहों में बँटकर इसी आँवले से एक दूसरे पर प्रहार करते हैं। जनमान्यता है कि आँवरामार के दौरान प्रसाद स्वरूप चढ़ाए गए आँवले की मार से व्यक्ति वर्ष भर निरोगी रहता है।

होलिका दहन की कथा

बस्तर में होलिका दहन की कथा भक्त प्रहलाद और होलिका से नहीं जुड़ी है बल्कि यह बस्तर की एक राजकुमारी से जुड़ी है जिसका नाम अज्ञात है। जनश्रुति है कि किसी आक्रमणकारी से बचने के लिए उस राजकुमारी ने आग में कूदकर जान दे दी थी। दंतेवाड़ा के शनि मंदिर के निकट सती शिला स्थापित है जिसे इसी राजकुमारी का स्मृति चिन्ह माना जाता है। इस शिला के सामने मंदिर में सुरक्षित रखे गए ताड़ के पत्तों से होली जलाई जाती है। परंपरानुसार इस दौरान उस आक्रमणकारी को गाली दी जाती है जिसके कारण राजकुमारी ने आत्मदाह किया था।

रंगभंग व देवी देवताओं की विदाई

फागुन मड़ई के अंतिम चरण में होलिका की राख, माई दंतेश्वरी मंदिर की मिट्टी तथा टेसू के फूलों से बनाए गए प्राकृतिक रंगों से मेंढका डोबरा मैदान में स्थित मावली गुड़ी में होली खेली जाती है जिसे रंगभंग कहा जाता है। मान्यता है कि इस अवसर पर माई दंतेश्वरी अन्य देवी-देवताओं के साथ होली खेलती हैं। पुजारी सहित सभी सेवादार इस आयोजन में शामिल होते हैं। रंगभंग के पश्चात शंकनी-डंकनी नदी के संगम पर पादुका पूजन का आयोजन किया जाता है। यहाँ लोगों पर अभिमंत्रित जल का छिड़काव किया जाता है। इसके बाद आमंत्रित देवी देवताओं की विदाई के साथ फागुन मड़ई उत्सव संपन्न होता है।

प्रदेश में विष्णु का सुशासन पहुँचेगा जन जन तक

8 अप्रैल से 31 मई तक प्रदेशव्यापी आयोजन, तीन चरणों में चलेगा अभियान

| जनमन रिपोर्ट |

छत्तीसगढ़ सरकार अप्रैल और मई महीने में सुशासन तिहार मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सुशासन की स्थापना का संकल्प लेकर सरकार निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में जुटी है। इसी क्रम में अब विष्णु के सुशासन को जन-जन तक ले जाने के लिए सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है। सुशासन तिहार-2025 का उद्देश्य है आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करना, शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना तथा विकास कार्यों में गति लाने के साथ ही आम जनता, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से सीधा संवाद स्थापित करना। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 8 अप्रैल को सुशासन तिहार की शुरुआत की है। सुशासन तिहार तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इस विशेष अभियान के लिए प्रदेश भर में विशेष प्रबंध किए गए जा रहे हैं, ताकि सुशासन को बल मिले, जनता की समस्याओं का शीघ्रता से समाधान हो। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारी सरकार सुशासन की स्थापना को लेकर लगातार काम कर रही है। शासन प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर शासकीय काम-काज में पारदर्शिता आए, शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो, इसका लाभ समाज के उन वर्गों को तत्परता से मिले जिनके लिए योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, इसे लेकर पहल की जा रही है। ज्ञात हो कि सुशासन तिहार 2025 के संबंध में एनआईसी ने sushasantihar.cg.nic.in/ पोर्टल भी विकसित किया है। तिहार संबंधित सभी जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

सुशासन तिहार-2025 के घटक

आवेदन प्राप्त करना

प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक आम जनता से आवेदन लिए जाएँगे। आवेदन नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों अथवा पोर्टल पर ऑनलाइन दिए जा सकते हैं। विकासखंडों और जिला मुख्यालयों में भी आवेदन के लिए समाधान पेटी रखी जाएगी। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड कर और आवेदक को पावती दी जाएगी। आवेदन लिखने के लिए जनता की सहायता करने के लिए कलेक्टर अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी लगायी गई है।

आवेदनों का निराकरण

सभी आवेदनों को संबधित विभागीय अधिकारियों को भेज कर एक महीने में निराकरण करने की समय सीमा तय की गई है। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला व राज्य स्तर पर किया जाएगा।

समाधान शिविरों का आयोजन

5 से 31 मई तक प्रत्येक 8 से 15 पंचायतों के बीच तथा नगरीय निकायों में भी समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसमें आवेदकों को उनके आवेदन के संबंध में जानकारी दी जाएगी। शिविर की जानकारी आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से या आवेदन की पावती के माध्यम से दिया जाएगा। आवेदनों का शिविर में निराकरण किया जाएगा, यह संभव न हुआ तो एक माह में निराकरण कर पोर्टल में दर्ज किया जाएगा। शिविरों में शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव समेत राज्य शासन के अधिकारी उपस्थित रहेंगे तथा आवेदकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का निराकरण हुआ या नहीं यह जानकारी लेंगे।

अटल निर्माण वर्ष

छत्तीसगढ़ राज्य इस वर्ष अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल विहारी बाजपेयी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। इस वर्ष को सरकार अटल निर्माण वर्ष के रुप में भी मना रही है। सुशासन की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में सुशासन तिहार-2025 का आयोजन महत्वपूर्ण पहल है।

गर्मी में ठंडक देने वाला छत्तीसगढ़ी स्वाद

| जनमन रिपोर्ट |

छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक खानपान के लिए जाना जाता है। गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग ऐसे व्यंजन पसंद करते हैं जो शरीर को ठंडक दें, पाचन में हल्के हों और पोषण से भरपूर हों। इस रिपोर्ट में हम कुछ प्रमुख छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की विशेषताओं, उनकी विधि, उनके स्वास्थ्यगत लाभ, आवश्यक सामग्रियों और प्रमुख क्षेत्रों का बिंदुवार विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक ग्रीष्मकालीन व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी होते हैं। ये व्यंजन शरीर को प्राकृतिक रूप से ठंडक प्रदान करते हैं, पाचन में सहायता करते हैं और गर्मी के मौसम में ताजगी बनाए रखते हैं। इन व्यंजनों का सेवन कर हम अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हुए सेहतमंद जीवनशैली अपना सकते हैं।

बोरे बासी

खासियतः यह पका हुआ चावल होता है, जिसे रातभर पानी में भिगोकर रखा जाता है और सुबह इसका सेवन किया जाता है। यह पाचन के लिए बहुत हल्का और गर्मी में ठंडक देने वाला व्यंजन है।

विधिः रात में बचे पके चावल को पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इसे नींबू, नमक, कच्चे प्याज, हरी मिर्च और सरसों के तेल के साथ खाया जाता है।

स्वास्थ्यगत लाभ

- पाचन को दुरुस्त रखता है।
- पेट को ठंडक पहुँचाता है।
- प्री-बायोटिक्स से भरपूर, आँतों के लिए लाभकारी है।

आवश्यक सामग्रीः पका हुआ चावल, पानी, नमक, सरसों तेल, हरी मिर्च, प्याज, नींबू।

प्रमुख क्षेत्रः बस्तर, जशपुर व छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खाया जाता है।

तीखुर शरबत

खासियतः तीखुर एक प्रकार का स्टार्च होता है जो गर्मी में ठंडक देने के लिए जाना जाता है। यह शरीर में गर्मी को कम करता है और हाइड्रेशन बनाए रखता है।

विधिः तीखुर पाउडर को पानी में अच्छे से घोल लें। इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर ठंडा परोसें।

स्वास्थ्यगत लाभ

- शरीर की गर्मी को कम करता है।
- लू से बचाव करता है।
- पाचनतंत्र को स्वस्थ रखता है।

आवश्यक सामग्रीः तीखुर पाउडर, पानी, गुड़ या शक्कर।

प्रमुख क्षेत्रः बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में यह विशेष रूप से प्रचलित है।

बेल शरबत

खासियत: बेल फल से बनाया जाने वाला यह शरबत गर्मी के मौसम में अत्यंत लाभकारी होता है। यह पेट की समस्याओं से राहत देता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।

विधि: बेल फल को तोड़कर उसका गूदा निकाल लें। इसे पानी में घोलकर छान लें। इसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर ठंडा परोसें।

स्वास्थ्यगत लाभ

- पेट की गर्मी को कम करता है।
- पाचन में सहायक होता है।
- डिहाइड्रेशन से बचाव करता है।

आवश्यक सामग्री: पका हुआ बेल फल, पानी, गुड़ या शक्कर।

प्रमुख क्षेत्र: यह बिलासपुर, रायगढ़ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोकप्रिय है।

कुसुम्बी शरबत

खासियत: यह कुसुम के बीजों से बनाया जाने वाला पेय है जो गर्मी में शरीर को ठंडक प्रदान करता है। यह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक हर्बल ड्रिंक्स में से एक है।

विधि: कुसुम के बीजों को रातभर पानी में भिगो दें। सुबह इसे छानकर शक्कर या गुड़ के साथ घोलकर पिएँ।

स्वास्थ्यगत लाभ

- शरीर को ठंडा रखता है।
- हाइड्रेशन बनाए रखता है।
- रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।

आवश्यक सामग्री: कुसुम के बीज, पानी, गुड़ या शक्कर।

प्रमुख क्षेत्र: यह सरगुजा और जशपुर जिले में अधिक खाया जाता है।

छाछ रोटी (रोटी पेज)

खासियत: यह गेहूँ की रोटी को पानी या मट्ठे में भिगोकर बनाया जाता है। इसे गर्मी के मौसम में ठंडक के लिए खाया जाता है।

विधि: बची हुई रोटी को छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। इसे मट्ठे या पानी में भिगो दें। स्वाद के लिए नमक, हरी मिर्च और प्याज डालें।

स्वास्थ्यगत लाभ:

- शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है।
- पाचन को सही रखता है।
- पेट की गर्मी को कम करता है।

आवश्यक सामग्री: गेहूँ की रोटी, मट्ठा या पानी, नमक, हरी मिर्च, प्याज

प्रमुख क्षेत्र: यह दुर्ग, राजनांदगाँव और रायपुर में अधिक खाया जाता है।

छत्तीसगढ़ : ढोकरा शिल्प

छत्तीसगढ़ का ढोकरा शिल्प हाल ही में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैंक्रो को ढोकरा शिल्प भेंट किया। ढोकरा शिल्पकला छत्तीसगढ़ की सदियों पुरानी धातु ढलाई शिल्पकला है जिसमें पीतल और ताँबे की मूर्तियाँ बनाने के लिए लुप्त मोम तकनीक का उपयोग किया जाता है। पीएम मोदी ने जो उपहार दिया उसमें पारंपरिक संगीतकारों को गतिशील मुद्राओं में ढाला गया है। यह कृति आदिवासी जनजीवन में संगीत के गहन सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित करती है। ढोकरा प्राचीन बेल मेटल शिल्प का एक रुप है जिसका उपयोग छत्तीसगढ़ के धातु कारीगरों द्वारा किया जाता है। मोहन जोदड़ो की नर्तकी अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन ढोकरा कलाकृति है।

छत्तीसगढ़ बना सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य

छत्तीसगढ़ जीएसटी संग्रहण में सबसे तेजी से प्रगति करने वाला राज्य बन गया है। वर्ष 2024-25 में राज्य ने जीएसटी संग्रहण में 18 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि दर्ज की है। इस वर्ष कुल 16390 करोड़ का जीएसटी संग्रहण किया गया है। देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जीएसटी संग्रहण इस अवधि में क्रमशः 15 व 16 प्रतिशत ही रहा है।

छत्तीसगढ़ हॉकी टीम डिवीजन बी में पदोन्नत

छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश ने 15 वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में डिवीजन सी से बी में पदोन्नति हासिल की है। छत्तीसगढ़ ने हॉकी हिमाचल को 3-2 से हराकर शीर्ष स्थान हासिल किया।

पूर्वोत्तर राज्यों में एएफएसपीए का विस्तार

केंद्र सरकार ने मणिपुर सशस्त्र बल के तहत विशेष शक्तियाँ अधिनियम (एएफएसपीए) को छह माह के लिए बढ़ा दिया हैं। इसमें पाँच जिलों के 13 पुलिस थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल नहीं हैं। केंद्र ने नगालैड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में एएफएसपीए को 30 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। एएफएसपीए कानून 1958 में संसद से पारित किया गया था। इसका उपयोग उन पूर्वोत्तर राज्यों बढ़ती हिंसा की रोकथाम के लिए किया गया था जिसपर नियंत्रण करने में राज्य सरकारें असमर्थ थीं। इस अधिनियम के तहत सशस्त्र बलों को विधिक कार्रवाई से संरक्षण प्राप्त है।

स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महान स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि पर 30 मार्च को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

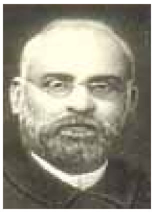

श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात में हुआ था। उन्होंने 1905 में लंदन में इंडियन होमरूल सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य युवा भरतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना था। वह बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष थे और वीर सावरकर से प्रभावित थे। बाद में वह पेरिस चले गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिनेवा में बस गए। 30 मार्च 1930 को उनकी मृत्यु हुई।

डॉ.राम मनोहर लोहिया की जयंती

23 मार्च को डॉ.राम मनोहर लोहिया की जयंती मनाई गई। डॉ.लोहिया का जन्म 1910 में हुआ था। वह भारत के समाजवादी आंदोलन तथा स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख व्यक्ति थे। 1934 में वह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बने। लोहिया ने द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटिश भागीदारी का विरोध किया। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल जाना पड़ा। 1952 में वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 1955 में समाजवादी हैदराबाद में एकत्र हुए और यहाँ लोहिया की अध्यक्षता में एक नई सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया जो 1964 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई। 1963 में लोहिया लोकसभा के सदस्य बने। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करते हुए सप्त क्रांति का समर्थन किया और विकेन्द्रित शासन के लिए चौखम्भा राज का प्रस्ताव रखा।

म्यांमार में भूकंप की विभीषिका

म्यांमार में हाल ही में 7.7 तीव्रता का भीषण भूकंप आया जिससे व्यापक विनाश हुआ है। भूकंप की यह घटना सागाइंट फाल्ट के साथ स्ट्राइक स्लिप फाल्टिंग के कारण हुई। म्यांमार में 1500 किमी में विस्तृत सागाइंट फाल्ट पश्चिम में भारतीय प्लेट तथा पूर्व में यूरेशियन प्लेट के बीच टेक्टोनिक सीमा का निर्धारण करता है। यह विश्व के सर्वाधिक सक्रिय नतिलंब सर्पण भ्रंश में से एक है। यह भूकंप भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के बीच हुए संचलन के कारण हुआ जिसमें भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के सापेक्ष उत्तर की ओर बढ़ रही थी।

पीएम मोदी ने किया पंबन ब्रिज का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत में बुनियादी ढाँचे के विकास में एतिहासिक उपलब्धि है। यह देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है जो सौ साल पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेगा। यह पुल रामेश्वरम द्वीप को मांडपम या मुख्य भूमि से जोड़ता है। 2.7 किमी लंबे पंबन ब्रिज का निर्माण 700 करोड़ की लागत से किया गया है।

सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 286 दिनों के बाद 19 मार्च को पृथ्वी पर वापस लौट आए। उनकी वापसी स्पेसएक्स के ड्रैगल कैप्सूल के जरिए हुई जो फ्लोरिडा तट के पास स्पलैशडाउन हुआ। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 5 जून 2024 को स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे लेकिन तकनीकी खराबी के कारण उन्हें 9 महीने अंतरिक्ष में ही रहना पड़ा। सुनीता ने अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक स्पेस वाक का रिकार्ड बनाया जो 62 घंटे 6 मिनट का है।

कोहली टी-20 क्रिकेट में 13000 रन बनाने वाले पहले भारतीय

विराट कोहली टी-20 क्रिकेट में 13000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। यह उपलब्धि उन्होंने आईपीएल में रायल चैलेंजर्स बेंगलुरू और मुंबई इंडियन्स के बीच हुए मैच के दौरान हासिल की। वह दुनिया के पाँचवें ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। कोहली ने 386 मैचों में यह उपलब्धि हासिल की है। उनसे पहले क्रिस गेल ने 381 मैचों में यह कारनामा किया है।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भारत को पहला स्वर्ण पदक

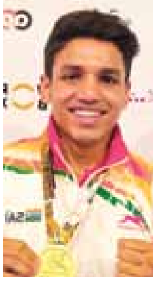

भारत की मुक्केबाजी टीम ने ब्राजील के फॉज डू इगुआसू में आयोजित 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में शानदान प्रदर्शन किया। हितेश गुलिया ने इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। वह इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। हितेश के अलावा अभिनाश जाम्वाल ने 65 किग्रा वर्ग में रजत पदक हासिल किया। चार अन्य भारतीय मुक्केबाजों ने विभिन्न भार वर्गों में कांस्य पदक अपने नाम किए। भारत ने कुल छह पदकों के साथ प्रतियोगिता का समापन किया जो उल्लेखनीय उपलिब्ध रही।

एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत को मिले 10 पदक

भारत ने अम्मान में आयोजित 2025 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 10 पदक जीते। दीपक पुनिया और उदित ने रजत पदक हासिल किया। दिनेश, मुकुल दहिया ने भी कड़ी टक्कर दी लेकिन स्वर्ण पदक से चूक गए। मनीषा भनवाला ने 62 किग्रा महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ऋतिका हुड्डा 76 किलो, उदित 61 किलो फ्रीस्टाइल, दीपक पुनिया पुरूष फ्रीस्टाइल 92 किलो ने रजत पदक जीता। अंतिम पंघाल, मंसी लाठर, मुस्कान, दिनेश कुमार, नितेश ने कांस्य पदक पर कब्जा किया।

भारत ने जीती आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी

भारतीय क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए तीसरी बार आईसीसी चैपियंस ट्राफी का खिताब जीत लिया। रोमांचक फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराकर भारत ने यह खिताब अपने नाम किया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए थे जिसे छह विकेट खोकर भारत ने हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रहे जबकि प्रतियोगिता में सर्वाधिक 263 रन बनाने वाले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र प्लेयर आफ टूर्नामेंट बने।

सुशासन तिहार बनेगा विकसित छत्तीसगढ़ का आधार

छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार प्रदेश में आठ अप्रैल से "सुशासन तिहार" मना रही है। तीन चरणों में संपन्न होने वाले "सुशासन तिहार" का आवेदन प्राप्त करने का पहला चरण (8 से 11 अप्रैल) है। दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया, जबकि तीसरे चरण में 05 से 31 मई तक समाधान शिविर का आयोजन होगा, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी समेत राज्य शासन का पूरा अमला शहर से लेकर गाँव तक मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशा के अनुरूप यदि राज्य की प्रशासनिक मशीनरी "सुशासन तिहार" को कायदे से मूर्त रूप दे दे तो यह विकसित छत्तीसगढ़ @2047 का आधार साबित होगा और वर्ष 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का सपना पूरा भी हो सकता है।

डॉ. संजय शेखर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार-"सुशासन किसी भी देश की प्रगति की कुंजी है।" पीएम आगे जोड़ते हैं- "सुशासन केवल एक दर्शन नहीं रह सकता। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।" सीएम विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में चल रहा "सुशासन तिहार" पीएम मोदी के उपरोक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया एक ठोस कदम है। भारतीय शासन प्रणाली में वैदिक काल से ही सुशासन की अवधारणा मौजूद रही है। यही वजह है कि आक्रांताओं के शासनकाल को छोड़ दें तो भारतीय शासन के केंद्र में सदा से मनुष्यता और नागरिकों के लिए मंगलकारी भावनाएँ विद्यमान रही हैं। मौर्य काल में भी चाणक्य ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में सुशासन का विस्तार से उल्लेख करते हुए लिखा है कि सुशासन का आधार नागरिक केन्द्रित प्रशासन है।

सुशासन के पाँच सिद्धांत के रूप में (SMART) को परिभाषित किया गया है। जिसमें सिंपल यानी आसान, मोरल यानी नैतिक, अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, रिस्पांसिबल यानी जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी सरकार को सुशासन की सरकार कहा गया है।

राज्य की विष्णु देव साय सरकार ने सुशासन के SMART रूल का अनुसरण करते हुए पिछले करीब 15 माह में अपनी सरकार को आसान, नैतिक, उत्तरदायी, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने की दिशा में ठोस काम शुरू किए हैं। इसके तहत भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति, शासन को पारदर्शी बनाने के लिए ई-ऑफिस प्रणाली को अपनाया जाना, डीबीटी के माध्यम से हितग्राहियों को सीधा लाभ पहुँचाना, लालफीताशाही पर लगाम लगाने के लिए सरकारी कार्यालयों में वरिष्ठ अफसरों के अटेंडेंस, ई-नोटशीट के माध्यम से सरकारी कामकाज का किया जाना समेत कई अन्य नवाचार शामिल हैं।

गौरतलब है कि तमाम कोशिशों के बावजूद कई बार सरकार की मंगलकारी और शुभता की मंशा पर सिविल सेवकों की मनोवृत्ति, जवाबदेही का अभाव, लालफीताशाही, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में निम्न जागरुकता और कानूनों तथा नियमों का अप्रभावी होना, सुशासन की पूरी प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं। ऐसे में सुशासन की मंशा को फलीभूत करने के लिए "सुशासन तिहार" जैसे आयोजनों की जरूरत होती है। चूँकि "सुशासन तिहार" तीन चरणों में संपन्न होने वाला एक समयबद्ध आयोजन है। लिहाजा प्रशासनिक महकमे की जिम्मेदारी है कि उसे समय सीमा में पूर्ण करना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों को न केवल समय सीमा में आवेदन लेना है बल्कि समय सीमा में उसका निराकरण भी करना है। उससे आगे यह कि यदि निराकरण नहीं होता है तो जनता के पास राज्य के मुखिया समेत प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रियों, अन्य जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से सीधा संवाद करने का भी अवसर मौजूद है। लिहाजा जायज समस्याओं और माँगों के निराकरण में लेटलतीफी की गुंजाइश नहीं के बराबर है।

राज्य जब विजन@2047 को अंतिम रूप दे रहा है ऐसे समय में "सुशासन तिहार" के तीसरे चरण में सरकार और राज्य की जनता का सीधा संवाद होना विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार करने की दिशा में एक बहुत ही शुभ और सकारात्मक कदम साबित हो सकता है। इस दौरान सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा भी होगी और विकास कार्यों में गति लाने के लिए जरूरी निर्देश भी दिए जायेंगे। राज्य के मुखिया विष्णु देव साय समेत सरकार के विभिन्न अंगों के साथ समाधान शिविर में आम जनता से होने वाले संवाद के माध्यम से सरकार को कई अहम सुझाव के साथ ही अन्य महत्वपूर्ण फीडबैक भी प्राप्त होगा जो विकसित छत्तीसगढ़ के लिए बनाई जाने वाली अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकती है।

लेखक- वरिष्ठ पत्रकार और भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के पोस्ट डॉक्टोरल फेलो हैं।

तैयारी का समय, अवसर की दस्तक

छत्तीसगढ़ व्यापमं से आयोजित होने वाली परीक्षाएं

। जनमन रिपोर्ट ।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने वर्ष 2025 के लिए विभिन्न विभागों में सरकारी नियुक्तियों हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह वार्षिक कैलेंडर प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए नई उम्मीदों और अवसरों का संदेश है। व्यापमं द्वारा जारी की गई सूची में प्रयोगशाला सहायक, सांख्यिकी अधिकारी, उप अभियंता, ADEO, पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, स्वास्थ्य संयोजक सहित कई प्रमुख पदों की संभावित परीक्षा आयोजित की जा रही है।

मुख्य परीक्षाओं की संभावित तिथियाँ इस प्रकार हैं

परीक्षा	संभावित तिथि
सहायक सांख्यिकी अधिकारी (KASO23)	13 अप्रैल 2025
उप अभियंता सिविल/विद्युत/यांत्रिकी (जल संसाधन विभाग)	20 जुलाई 2025
उप अभियंता सिविल/विद्युत/यांत्रिकी (लोक निर्माण विभाग)	13 जुलाई 2025
सहायक विकास विस्तार अधिकारी (ADEO)	15 जून 2025
पुलिस कांस्टेबल	14 सितंबर 2025
स्टाफ नर्स	21 सितंबर 2025
वार्ड बॉय एवं वार्ड आया	12 अक्टूबर 2025
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष/महिला)	9 नवंबर 2025
लेखन/सामग्री विभाग के विभिन्न पद	30 नवंबर 2025
जल संसाधन विभाग के अन्य पद	7 दिसंबर 2025
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय भर्ती	14 दिसंबर 2025

परीक्षा आयोजन और तैयारी के पहलू

छत्तीसगढ़ व्यापमं द्वारा घोषित यह कैलेंडर पारदर्शिता और पूर्व-योजना का परिचायक है। इससे अभ्यर्थियों को समयबद्ध और व्यवस्थित तैयारी करने का पूरा अवसर मिलता है। वर्ष 2024 के अंतिम महीनों से ही कोचिंग संस्थान, शिक्षक और परीक्षार्थी इस कैलेंडर के आधार पर सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज, और मॉक टेस्ट की तैयारी में लग चुके हैं। राज्य शासन द्वारा चयन प्रक्रिया को त्वरित और निष्पक्ष बनाने के लिए इस वर्ष ऑनलाइन आवेदन प्रणाली, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, और उत्तर पुस्तिकाओं की डिजिटल स्कैनिंग की सुविधा भी सुनिश्चित की जा रही है।

दिशा-निर्देश और आवश्यक जानकारियाँ

1 **ऑनलाइन आवेदनः** सभी परीक्षाओं के लिए आवेदन केवल व्यापमं की आधिकारिक वेबसाइट https://vyapam.cgstate.gov.in पर ही किए जाएँगे।

2 **ऑनलाइन आवेदनः** आवेदन के समय शैक्षणिक प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र आदि किसी की कॉपी अपलोड नहीं करना होता है।

A **प्रोफाइल पंजीकरण...** व्यापम की परीक्षाओं में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी को एक बार प्रोफाइल पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है..

3 **परीक्षा प्रवेश पत्रः** परीक्षा तिथि से लगभग 7 दिन पहले प्रवेश पत्र वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे।

4 **मास्क और कोविड सतर्कताः** यदि आवश्यक हो, तो परीक्षार्थियों को स्वास्थ्य दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

5 **भाषा माध्यमः** परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा (जहाँ लागू हो)।

6 **उत्तर कुंजी और आपत्तिः** परीक्षा के बाद व्यापमं द्वारा प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, जिस पर अभ्यर्थी ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे।

तैयारी ही सफलता की कुंजी है

वर्ष 2025 का यह कैलेंडर न केवल भर्ती प्रक्रिया को अनुशासित करता है, बल्कि युवाओं को अवसर की स्पष्टता भी देता है। समय पर परीक्षा तिथियों की घोषणा से पारदर्शिता और योजनाबद्ध तैयारी को बल मिलेगा। परीक्षार्थियों को अब चाहिए कि वे अपने स्वप्नों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी लगन से पढ़ाई करें और इस सुनहरे अवसर का भरपूर लाभ उठाएँ।

छत्तीसगढ़ी कहानी

लीलागर

एक झन निःसंतान दंपति रहंय। गाँव के मुखिया रहे, अन्न-धन, जमीन-जायदाद के कछु कमी नइ रहे। फेर, विधाता हर हरेक के भाग म जम्मों जीनिस नइ लिखे रहय, कछु-न-कछु कमी कर देहे रथे। वइसने कमी ओकरो जीनगी म रथे। धन-दौलत भरे रथे फेर बाल-बच्चा बर तरसत रथें। कतको पूजा-पाठ, ब्रत-उपवास, प्रार्थना करथें भगवान के। ओकर गोसाईन हर शंकर भगवान के रोज पूजा करय दूध-जल चढ़ा के रोज एक ठन बेटा के आशीष माँगय। आखिर म कई बछर बाद भगवान महादेव ओकर प्रार्थना ल सुनथे अउ ओकर ऊपर कृपा करथे।

भगवान के कृपा ले ओकर एक ठन सुग्घर रुप म बेटा होथे। नाम रखथें 'अगरदास'। बेटा ल देख-देख के ओमन के खुशी के ठिकाना नइ रहय। जइसने-जइसने वो बाढ़त जात रहे ओकर सुघरई हर देखते बनत रहय। माँ-बाप ओकर चोनहा देख सब भूला गय रहें। चोनहा देखत कब दिन हर कइसे निकलगे कुछ पता नइ चलीस बेटा बाढ़िस त जगह-जगह ले सगा-पहुना के शोर-पता आय लागीस। एक ठन सुग्घर कन्या ल देख के ओकर बिहाव तय होगे। कन्या के नाव रहे 'लीला'।

बिहाव बढ़िया ढंग ले निपट गे बहु घर आगे, बहु के रुप-रंग ल देख के अगर के महतारी गद् गद् हो जात रहे मने-मन फूले नइ समावत रहे। कब ले ये दिन ल देखे बर तरसत रहीस हे जब ले बेटा जनमें रहे ओकर बिहाव के सपना देखत रहीस। बिहाव निपटीस सब पहुना मन चल दीन त अगर के महतारी सोंचथे- महादेव के किरपा ले बेटा ले पाय रहें ओकरे किरपा ले आज बहु मिले हे। बर-बिहाव सुग्घर निपट गीस त बेटा-बहु ल शंकर भगवान के पूजा-दर्शन करवा देंव। महादेव ल मनाय रहें, मोर बेटा बने बाढ़-पोढ़ जाय, बने-बने ओकर बर-बिहा हो जाय त बेटा-बहू दूनों ल ओकर शरण म ले के आहूँ। ये बात ल सुरता करके, बेटा-बहु दूनो ल तियार करथे, परात म पूजा-पाठ के सामान ल धरथे अऊ बेटा-बहु ल ले के भगवान शंकर मेर जाथे ओकर जलहरी के अभिषेक-पूजा करवाथे। पूजा करके बेटा-बहु दूनो ल महादेव म ढोंकरे बर कथे, दूनों ढोंकरथें तंह ले महतारी हर महादेव करा ओमन बर आशीष माँगथे। महादेव तुंहर आशीर्वाद ले बेटा पाय रहें आज तुंहरे आशीर्वाद ले सुग्घर बहु मिलीस हे, दूनों ल तुंहर शरण म ले के आय हँव, किरपा करके ये मन ल अपन म शरण म ले लेवा, आज ले येमन तुंहर सेती यें। महतारी हर बेटा-बहु बर आशीर्वाद माँगथे ओतके बेरा वहाँ से एक ठन जलधारा प्रस्फुटित होथे अउ बेटा-बहु दूनों ल अपन लपेटा म ले लेथे।

महतारी सन्न रह जाथे। बेटा-बहु दूनों धार संग बोहावत रथें, महतारी आवाज लगाथे लीला-अगर, लीला-अगर। लीला-अगर बोहावत रहें, महतारी हर जलधारा के किनारे-किनारे बदहवास दंउड़त रहय, मोर लीला-अगर बोहागे-मोर लीला-अगर बोहागे। देखते-देखते लीला-अगर वो जल-धारा म समा जाथें। अब तक जल-धारा नदी के रुप ले ले रथे। महतारी हर अपन सुध-बुध खो के सब झन ल ओ नदी ल बतावय मोर लीला-अगर बोहा गे। मोर लीला-अगर बोहावत हे। सब ल लगे ओहर नदी के बारे म कहत हे सब कहें हाँ 'लीलागर बोहावत हे'।

सनद रहे

अप्रैल के खास दिन

दिनदर्शिका

श्रीराम नवमी : 06 अप्रैल
कामदा एकादशी : 08 अप्रैल
महावीर जयंती जैन : 10 अप्रैल
श्री हनुमान प्रकटोत्सव : 12 अप्रैल
वरुथिनी एकादशी : 24 अप्रैल
अक्षय तृतीया : 30 अप्रैल
श्री परशुराम प्रकटोत्सव : 30 अप्रैल

जयंती

पं. माखनलाल चतुर्वेदी : 04 अप्रैल
जगजीवन राम : 05 अप्रैल
घनश्यामदास बिड़ला : 10 अप्रैल
महात्मा ज्योतिबा फुले : 11 अप्रैल
राणा सांगा : 12 अप्रैल
डॉ. भीमराव आम्बेडकर : 14 अप्रैल
गुरु तेग बहादुर : 18 अप्रैल
वल्लभाचार्य : 24 अप्रैल
दामोदर गणेश बापट : 29 अप्रैल

बलिदान दिवस

मंगल पाण्डे : 08 अप्रैल
तात्या टोपे : 18 अप्रैल

पुण्यतिथि

बंकिमचंद्र चटर्जी : 08 अप्रैल
मोरारजी देसाई : 10 अप्रैल
फणीश्वरनाथ रेणु : 11 अप्रैल
मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया : 14 अप्रैल
डॉ राधाकृष्णन : 17 अप्रैल
रामधारी सिंह दिनकर : 24 अप्रैल
बाजीराम पेशवा प्रथम : 28 अप्रैल

दिवस

विश्व स्वास्थ्य दिवस : 07 अप्रैल
जलियांवाला बाग दिवस : 13 अप्रैल
अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस : 22 अप्रैल
विश्व पुस्तक दिवस : 23 अप्रैल

आदिवासियों के दिलों का राजा
महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव

| जनमन रिपोर्ट |

एक राजा जिसने हमेशा अपनी आदिवासी प्रजा के जेहन में महाराजा के रुप में राज किया। बस्तर के स्वाभिमान और आदिवासी अस्मिता की रक्षा में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

बस्तर के महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव अपनी प्रजा के दिलों पर शासन करते थे। उनकी आवाज बनकर सत्ताधीशों की जनविरोधी नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते थे नतीजतन एक दिन उन्हें उनकी जनता सहित गोलियों से भून दिया गया। 25 मार्च को बलिदान दिवस मनाते हुए उन्हें याद किया गया। भंजदेव का जन्म 25 जून, 1929 को शिलांग में हुआ था। उनकी माता स्वर्गीय प्रफुल्ल कुमारी देवी बस्तर की महारानी थीं। 1936 में महारानी प्रफुल्ल देवी के निधन के बाद प्रवीर चंद्र भंजदेव को औपचारिक रूप से बस्तर रियासत की गद्दी पर बिठाया गया। प्रवीर चंद्र की उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुई थी। वे अर्थशास्त्र, भाषा विज्ञान, नृविज्ञान, दर्शन और संस्कृत के अच्छे जानकार व विद्वान थे।

भंजदेव ने आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने वाली शक्तियों के खिलाफ जमकर संघर्ष किया। इसे मालिक-मकबूजा भ्रष्टाचार कांड नाम दिया गया। राजा ने इस भ्रष्टाचार और संशोधन का व्यापक विरोध किया। एक तरह बस्तर में विद्रोह की स्थिति खड़ी हो गई। राजा के समर्थन में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। आदिवासियों में राजा के प्रति लोकप्रियता से चिढ़कर प्रशासन ने आदिवासियों का दमन करने का निश्चय किया। मार्च 1961 में बीस हजार आदिवासियों पर निर्ममतापूर्वक गोलियों की बौछार की गई, जिसमें अनेक आदिवासी मारे गये। इस बीच अनेक मुद्दों जबरन लेवी वसूली, आदिवासी महिलाओं से पुलिस का दुर्व्यवहार, भुखमरी, दण्डकारण्य प्रोजेक्ट इत्यादि पर भंजदेव का सरकार से सामना होता रहा। बस्तर के आदिवासी महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव को देवतुल्य मानते हैं। उनकी किताब 'आई प्रवीर -द आदिवासी गॉड' प्रसिद्ध है।

1957 में प्रवीर चंद्र भंजदेव विधायक बने तथा 1959 में ही इस्तीफा भी दे दिया। सन 1962 तक आते-आते वे पूरे देश के आदिवासियों के लिए एक आदिवासी पार्टी की नींव रखने के विषय में विचार करने लगे। इसी साल होने वाले विधानसभा में इनके साथियों ने विधानसभा चुनाव का सामना किया और बस्तर के दस विधानसभा सीटों में से 9 पर बड़ी जीत हासिल कर ली। उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से देश की सबसे बड़ी सत्ता परेशान हो गई। सरकार किसी तरह से इन समस्याओं से निजात पाना चाहती थी। इसी बीच 25 मार्च 1966 को एक घटना घट गई। पूरे बस्तर से बड़ी संख्या में आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर भंजदेव के समक्ष इकट्ठा हुए थे। इन्हीं लोग में से एक विचाराधीन कैदी को ले जाते समय पुलिस और आदिवासियों में झड़प हो गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने आनन-फानन में पूरे राजमहल को घेर लिया। सभी आदिवासी राजमहल के अंदर जा चुके थे। पुलिस ने सभी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। भंजदेव ने पहले महिलाओं और बच्चों को आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा। इस दौरान पुलिस ने निहत्थे औरतों और बच्चों पर फायरिंग शुरू कर दी, बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे मारे गये। राजमहल में घुसकर पुलिस ने अनेक आदिवासियों समेत महाराजा को भी गोलियों से भून दिया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि महाराजा भंजदेव न केवल बस्तर के गौरव थे, बल्कि जनजातीय अस्मिता, आत्मसम्मान और अधिकारों की आवाज़ भी थे। महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव जी ने बस्तर की जल, जंगल और ज़मीन के साथ-साथ जनजातीय समाज के हक और सम्मान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया।

बस्तर के स्वाभिमान और आदिवासी अस्मिता की रक्षा में महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव का बलिदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। अब उनके वंशज कमल चंद्र भंजदेव उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं।

Photo Of The Month

बस्तर में सिमटते नक्सलवाद से आम जनमानस में सुरक्षा का भाव जाग रहा है। एक समय में नक्सल आतंक से ग्रसित रहे बस्तर जिले के सांस्कृतिक गांव किलेपाल में अब पुनः अपनी आदिम संस्कृति की खुशबू महकने लगी है। इसी गांव में खिलखिलाता "दण्डामी माड़िया नर्तक दल" का जोड़ा।

तस्वीर भेजने वाले का नाम - अविनाश प्रसाद

आप भी भेजें तस्वीरें

इस कॉलम के जरिए हर महीने हम आपकी बेहतरीन तस्वीरों को हमारे मैगजीन के पेज पर प्रकाशित करेंगे और साथ ही देंगे एक खास इनाम!

भाग लेने के लिए आसान कदम

1. अपनी सबसे खास तस्वीर क्लिक करें–वह तस्वीर जो शासकीय योजना, सामाजिक बदलाव पर एक अनोखी कहानी कहती हो या आपको और प्रदेशवासियों को गर्व का अनुभव कराए।
2. हमें ई-मेल करें: अपनी तस्वीर हमें भेजें chhattisgarhjanman@gmail.com पर।
   - सब्जेक्ट लाइनः "फोटो ऑफ द मंथ एंट्री"
   - अपने नाम, पते और संपर्क नंबर के साथ फोटो अटैच करें।

क्या खास मिलेगा?

- चुनी गई तस्वीर को हमारी मैगजीन के "फोटो ऑफ द मंथ" कॉलम में स्थान मिलेगा।
- साथ ही विजेता को मिलेगा एक आकर्षक इनाम और प्रमाणपत्र।
- विजेता को मुख्यमंत्री से मिलने का भी अवसर मिलेगा।

चयन प्रक्रिया

- फोटो का चयन विशेष ज्यूरी टीम द्वारा किया जाएगा जो आपकी रचनात्मकता, विषय और प्रस्तुति को ध्यान में रखते हुए विजेता का चुनाव करेगी।
- तो देर किस बात की? अपनी कला को दुनिया के सामने लाने का मौका न गँवाएँ।
- अपनी तस्वीर आज ही भेजें और बनें "फोटो ऑफ द मंथ" के विजेता!

नियम व शर्तें

- फोटो साइज- 5 एमबी से अधिक होना चाहिए
- केवल मौलिक और स्वयं द्वारा खींची गई तस्वीरें ही स्वीकार होंगी।
- तस्वीरें किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए।
- ज्यूरी द्वारा विजेता का निर्णय अंतिम होगा।

हम आपकी तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं!

हमर चित्रकारी

बच्चों की कला, समाज के विचार से शुरू पेंटिंग ऑफ द मंथ का "हमर चित्रकारी" कॉलम!

- क्या आपके बच्चे के अंदर छिपा है एक हुनरमंद कलाकार?
- क्या उनकी तूलिका से उभरती हैं सामाजिक संदेश देने वाली पेंटिंग्स?

तो यह अवसर उनके लिए है! "छत्तीसगढ़ जनमन मासिक पत्रिका" लेकर आया है खास स्कूली बच्चों के लिए एक शानदार पहल – "पेंटिंग ऑफ द मंथ"।

ऐसे होगी थीम : "स्वच्छ भारत", "हमारा छत्तीसगढ़" "महिला सशक्तीकरण", "शिक्षा का महत्व", "पर्यावरण संरक्षण", "परंपरा एवं संस्कृति" आदि।

क्या करना होगा?

1. अपने बच्चे को इस थीम पर एक पेंटिंग बनाने के लिए प्रेरित करें।
2. पेंटिंग को स्कैन करें या फोटो लें।
3. हमें ईमेल करें:

chhattisgarhjanman@gmail.com

- सब्जेक्ट लाइन: "हमर चित्रकारी" पेंटिंग ऑफ द मंथ एंट्री।
- बच्चे का नाम, उम्र, कक्षा, स्कूल का नाम और माता-पिता का संपर्क नंबर जरूर भेजें।

विजेता को क्या मिलेगा?

- चुनी गई पेंटिंग को हमारी मैगजीन के "पेंटिंग ऑफ द मंथ" कॉलम में प्रकाशित किया जाएगा।
- विजेता को मिलेगा एक आकर्षक इनाम और सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट।
- अन्य प्रतिभागियों की पेंटिंग्स को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जा सकता है।
- विजेता को मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर या हेलीकॉप्टर राइड का भी अवसर मिल सकता है।

चयन प्रक्रिया: पेंटिंग का मूल्यांकन हमारी विशेष ज्यूरी टीम द्वारा किया जाएगा। कला, विषय से मेल और सामाजिक संदेश को ध्यान में रखते हुए विजेता का चयन होगा।

कुछ जरूरी बातें: पेंटिंग केवल स्कूली बच्चों (कक्षा [कक्षा सीमा लिखें, जैसे – 1 से 12 तक]) द्वारा बनाई जानी चाहिए। पेंटिंग पूरी तरह मौलिक होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया पारदर्शी और अंतिम होगी।

थीम: "परंपरा एवं संस्कृति", अक्षिता शर्मा, कक्षा 6 वीं, स्कूल- भारतीय विद्या भवन, सड्डू, रायपुर

4 | छत्तीसगढ़ी पहेली (चौखड़ी जनउला)

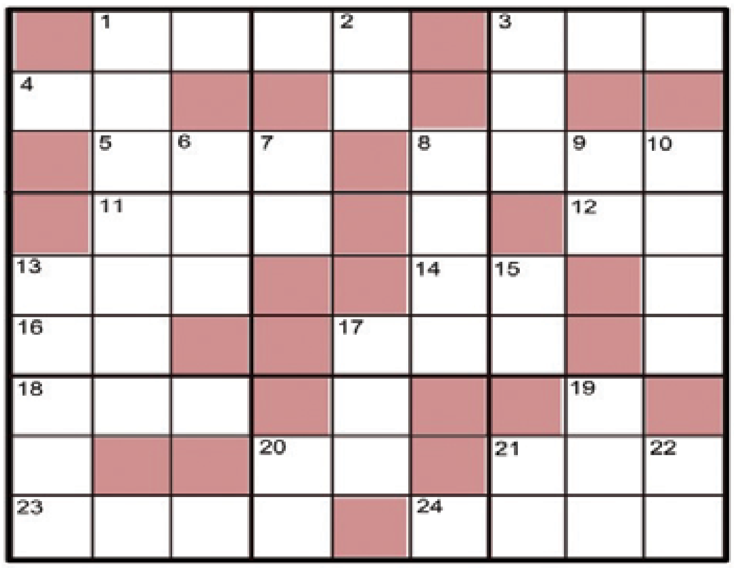

इस छत्तीसगढ़ी पहेली (चौखड़ी जनउला) में दाँए से बाँए और उपर से नीचे प्रश्न (जनउला) हैं वे हिन्दी में हैं जिसका उत्तर आपको चौखाने (चौखड़ी) में छत्तीसगढ़ी भाषा में देना है।

दायें से बांये:-

1. पसंद न करना, घृणा करना
3. उपकार, उपकृत होना
4. बुराई, दोष
5. दस के लिए प्रयुक्त शब्द
8. आलसी, यत्नपूर्वक, बड़ी मुश्किल से
११. गर्भनाल
१२. नीचे, आर्द्र, गीला
13. दर्द का कराह
14. छत्तीसगढ़ में लड़कियों द्वारा खेले जाने वाला एक खेल
16. दलहन का एक प्रकार
17. इच्छा, मर्जी, खुशामद, आवश्यकता, बादल का गर्जन
18. राजमिस्त्री का एक औजार, कर्मफल
20. मिट्टी के बर्तन को पकाने वाली भट्ठी
21. लाल रंग की मिट्टी की मटकी
23. लोकोक्ति, कहावत, मसल, सुभाषित
24. बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान

उपर से नीचे :-

1. बस्तर में शांति स्थापित करने हेतु सरकार की महत्वाकांक्षी योजना
२. लघु, अल्प वयस्क, क्षुद्र, नन्हा, छोटू
3. पूरी तरह से, सम्पूर्ण रूप से, पूर्णतः
6. हरण करना, ले लेना, छीनना, दूर करना
7. लाने का अनुरोध, ज्वालामुखी से निकलने वाला द्रव
8. लात खाने वाला, दुर्व्यसनी
9. मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा
10. अनसुनी करना, बहाना बनाना, बात बनाना, टालमटोल करना, सरकाना
13. वाग्युद्ध करने वाला, तर्क-कुर्तक करने वाला, बकवास करने वाला
१५. खोजने की क्रिया, शोध, अविष्कार
१७. गौ, धेनु, गाय
१९. नाला, जल निकास
२०, आम्र, आम
२१. अशांति, आकुलता, उद्विग्न
२२. पत्नी की बहन

3 | छत्तीसगढ़ी पहेली का उत्तर

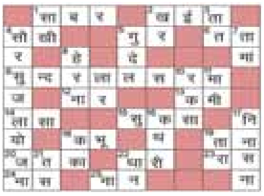

विजेता : धर्मेंद्र निर्मल
पता : दुर्ग

इसे सुलझाने के बाद इसकी तस्वीर खींचकर हमें ईमेल ***chhattisgarhjanman@gmail.com*** *करें। चयनित विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा।*

प्रगति पथ पर छत्तीसगढ़

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि की ओर

- देश में टीन धातु का नंबर वन उत्पादक राज्य
- देश में धान की सर्वाधिक किस्मों वाला राज्य
- जैव विविधता के साथ हरियाली में अग्रणीय राज्य
- कोयला उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
- सरप्लस बिजली उत्पादन के साथ देश का पावरहाउस
- लौह अयस्क उत्पादन में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य
- प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता में देश का सबसे संपन्न राज्य
- देश के कुल सीमेंट उत्पादन में 20% का योगदान देने वाला राज्य

हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in | ChhattisgarhCMO

सुशासन तिहार 2025

समस्याओं का समाधान

आपके शहर, आपके ग्राम

08 अप्रैल से 31 मई, 2025

प्रथम चरणः
समस्या संबंधी आवेदन
(08 से 11 अप्रैल, 2025)

द्वितीय चरणः
आवेदनों का निराकरण
(लगभग 01 माह)

तृतीय चरणः
समाधान शिविर
(05 से 31 मई, 2025)

संवाद से समाधान तक

श्री नरेंद्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

अधिक जानकारी के लिए स्कैन करें

मुद्रक एवं प्रकाशक - डॉ. रवि मित्तल, आयुक्त जनसंपर्क द्वारा जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एवं विश्व परिवार, 421, उरला इंडस्ट्रियल एरिया, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा मुद्रित, संपादक जवाहर लाल दरियो, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद।